नगर महापालिका, आगरा ने अपने कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए अपने ६४ वें अधिवेशन की चतुर्थ बैठक दिनांक १४-७-१९६४ के संकल्प संख्या ४ (१४) के अन्तर्गत पेन्शन नियमावली 'आगरा नगर महापालिका कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा विनियम १९६२' के नाम से जो उत्तर प्रदेश के राजपत्र (गजट) में विज्ञप्ति सं० २६१ जी० डी० एकाउन्ट्स दि० २८ दिसम्बर १९६४ द्वारा दि० ९-१-१९६५ में प्रकाशित हुई स्वीकार की थी। इस नियमावली में समय-समय पर निम्न प्रकार संशोधन भी हुए हैं :-

(१) प्रथम संशोधन विज्ञप्ति सं० ४१ जी० डी० एच० ओ० दिनांक १५-४-१९६६ द्वारा जो दिनाँक २३-४-१९६६ को राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

(२) द्वितीय संशोधन विज्ञप्ति सं० ५२१ जी० डी० एच० ओ० दिनांक ३०-३-१९६७ द्वारा जो दिनांक ८-४-१९६७ को राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

(३) तृतीय संशोधन विज्ञप्ति स० १०६६ जी० डी० एच० ओ० दि० ३-१०-१९६७ द्वारा जो दिनाक १४-१०-१९६७ को राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

(४) चतुर्थ संशोधन विज्ञप्ति सं० ४६० पी० एफ० एकाउन्ट्स (वि०) दिनांक १६-२- ९६७ द्वारा जो दिनांक २-३-१९६८ को राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

(५) पंचम संशोधन विज्ञप्ति सं० ५३ ओ० एकाउन्ट्स पी० एफ० एस० दिनांक १९-४-१९७४ द्वारा जो दिनांक २७-४-१९७४ का राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

(६) षष्ठम संशोधन विज्ञप्ति स० ९५ डी० एकाउन्ट्स पी० एफ० एस० दिनांक १२-८-१९७५ द्वारा जो दिनांक १५-११-१९७५ को राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

अब तक इस नियमावली की कोई ऐसी प्रति नहीं थी जिसमें समस्त संशोधन एवं मूलपाठ साथ-साथ हो इस कारण कभी-कभी नियमों के उल्लेख करने में भी कठिनाई होती थी। अतः इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु यह नियमावली पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित की जा रही है।

पुस्तक के मूल पाठ में संशोधित नियम तथा मोटी लकीर के नीचे संशोधन का प्रभावी दिनांक व पूर्व प्रचलित नियम, तदुपरान्त निर्धारित प्रपत्र तथा अन्त में परिशिष्ट में समय-समय पर किये गये प्रत्येक संशोधन का विवरण दिया गया है।

रामदास सिंहल
लेखा अधिकारी, नगर महापालिका
एवं
मुख्य लेखा अधिकारी, विकास प्राधिकरण,
आगरा।

दिनांक :—३१ मई १९७६

आगरा नगर महापालिका

कर्मचारी सेवा निवृत्ति वेतन तथा उपादान नियमावली

आगरा नगर महापालिका कर्मचारी सेवा निवृत्ति वेतन तथा उपादान नियमावली १९६२ जो उत्तर प्रदेश गजट के भाग ३ में दिनांक ६ जनवरी १९६५ को प्रकाशित प्रकाशन की तिथि से प्रभावी तथा समय-समय पर किए गये संशोधनों सहित :—

विनियम

शीर्ष नाम तथा प्रारम्भ :—

१ (१) इन विनियमों का नाम आगरा नगर महापालिका कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमैन्ट बैनीफिट) विनियम १९६२ होगा।

१ (२) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होंगे।

उपबन्ध यह है कि इन विनियमों की सुविधा महापालिका के उन कर्मचारियों को भी प्राप्य होगी जो १ फरवरी १९६० से इन विनियमों के प्रकाशन तिथि के अन्तर्कालीन अवधि में सेवा निवृत्ति हो गये हैं, यदि वे विनियमों की प्रकाशन तिथि के ३ मास के अन्दर लिखित रूप में इन विनियमों को अंगीकार करें और प्रकाशन तिथि से *२९ फरवरी १९६८ तक विनियमों की अन्य शर्तों की भी पूर्ति कर दें।

परिभाषायें :—

२—प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन विनियमों में :—

(१) अधिनियम (अथवा एक्ट) से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १९५९ (एक्ट २, १९५९)।

---

*यह संशोधन सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि १४ अक्टूबर १९६७ से लागू है। इससे पहले मूल नियम निम्न प्रकार था :—

उपबन्ध यह है कि इन विनियमों की सुविधा महापालिका के उन कर्मचारियों को भी प्राप्य होगी, जो १ फरवरी १९६० से इन विनियमों के प्रकाशन तिथि के अन्तर्कालीन अवधि में सेवा निवृत्त हो गये हैं, यदि वे विनियमों की प्रकाशन तिथि के तीन मास के अन्दर लिखित रूप में इन विनियमों को स्वेच्छा से अंगीकार करें और प्रकाशन तिथि के ६ मास के अन्दर विनियमों की अन्य शर्तों की भी पूर्ति कर दें।

इसके उपरान्त शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि २३ अप्रैल १९६६ से प्रभावी हुए उसमें यह तिथि ३० अप्रैल १९६६ की गई थी।

Scanned with OKEN Scanner

(२) औसत उपलब्धियों (ऐवरेज इमौल्यूमैन्ट्स) से तात्पर्य है सेवा निवृत्ति के मास से पूर्व *१२ मास में प्राप्त उपलब्धियों की औसत धनराशि यदि, इन १२ मासों में छुट्टी का समय भी सम्मिलित हो तो उस समय के लिये, अगर वह छुट्टी पर न हुआ होता तो स्थायी नियुक्ति के लिये जो उपलब्धियाँ प्राप्य (एडमिसिबिल) होती, वे उपलब्धियाँ उस समय की उपलब्धियाँ समझी जावेंगी।

प्रतिबन्ध यह है कि अधिनियम की धारा ५७७ (ङ) में वर्णित किसी अधिकारी के विषय में यदि वह नियत दिन से पूर्व स्थायी हो चुका हो, तो औसत उपलब्धियाँ निकालने के लिये नियत दिन के पहले तथा उसके बाद महापालिका के अन्तर्गत की गई सारी सेवा का समय, स्थायी नियुक्ति का समय तथा इस समय में उसे मिला वेतन स्थायी वेतन माना जावेगा।

(३) 'उपलब्धियाँ' (इमौल्यूमैन्ट्स) से तात्पर्य है :—

(क) वेतन फाइनैन्शियल हैन्डबुक (भाग २ से ४) वाल्यूम २ के फन्डामैन्टल रूल ९(२१) में परिभाषित तथा समय-समय पर संशोधित परिभाषा के अनुसार तथा ;

(ख) मंहगाई भत्ता अथवा तत्सम अन्य भत्ता, यदि कोई हो, जो अधिकारी को प्रतिमास उसकी सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु, जैसी भी दशा हो, के समय उसे प्राप्य (एडमिसिबिल) हो।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई अधिकारी सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु जैसी भी दशा हो, के समय छुट्टी पर हो तो वह उपलब्धियाँ (इमौल्यूमैन्टस) जो उसे प्राप्य होती, यदि वह उस समय अवकाश पर न होता, उपलब्धियाँ (इमौल्यू-मैन्टस) समझी जावेंगी।

२(४) परिवार में किसी अधिकारी के नीचे लिखे सम्बन्धी सम्मिलित होंगे :—

(क) धर्म पत्नी, पुरुष अधिकारी के सम्बन्ध में।
(ख) पति, स्त्री अधिकारी के सम्बन्ध में।
(ग) पुत्र
(घ) अविवाहित अथवा विधवा पुत्रियाँ।
इसमें सौतेले बच्चे और गोद लिये बच्चे भी सम्मिलित होंगे।

---

*यह संशोधन सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि १५ नवम्बर १९७५ से निर्णीत होने वाले मामलों पर लागू है इससे पहले औसत उपलब्धियों के आगणन के लिए ३६ मास का वेतन लिया जाता था।

(ङ.) भ्राता १८ वर्ष से कम आयु का तथा अविवाहित और विधवा बहिनें, जिनमें विमातृ भ्राता तथा विमातृ बहिनें सम्मिलित होंगी।

(च) पिता।

(छ) माता।

(ज) विवाहित पुत्रियाँ, जिनमें सौतेली लड़कियां सम्मिलित होंगी।

(झ) पूर्व मृत पुत्र के बच्चे।

२(५) अधिकारी से तात्पर्य महापालिका के किसी ऐसे कर्मचारी से है, जिसकी महापालिका के अन्तर्गत किसी स्थायी सेवा निवृत्ति वेतनीय (पेन्शनेबिल) पद पर नियुक्ति की गई हो तथा वह पद उस श्रेणी में आता हो, जिस पर यह विनियम लागू हो अथवा उसको ऐसे पद पर नियुक्त रहने का ग्रहणाधिकार हो यदि उसका गृहणाधिकार निलम्बित न कर दिया गया हो।

२(६) 'निवृत्त वेतनीय पद' (पेन्शनेबिल पोस्ट) से तात्पर्य है :—

(क) पूर्व नगरपालिका (म्युनिसिपल बोर्ड) तथा नगर सुधार प्रन्यास (इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट) का कोई स्थायी पद जिस पर भविष्य निधि की सुविधा प्राप्त हो और जो अधिनियम की धारा ५७७ (ङ) के अन्तर्गत महापालिका में बना रहे।

(ख) अधिनियम की धारा १०६ के अन्तर्गत महापालिका द्वारा सृजित कोई स्थायी पद।

२(७) 'व्यक्ति' में 'कम्पनी अथवा संघ (एसोसियेशन) अथवा व्यक्तियों का समूह, जिसका नियमन (इनकारपोरेशन) किया गया अथवा न किया गया हो, सम्मिलित है।

२(८) अर्हकारी सेवा (क्वालीफाइंग सर्विस) से तात्पर्य उस सेवा से है जो सिविल सर्विस रेगुलेशन के अन्तर्नियम (आर्टीकिल) ३६८ के अनुसार सेवा निवृत्ति वेतन प्राप्त करने के योग्य बनाती, यदि सम्बन्धित सेवा सरकार के अन्तर्गत होती तथा उस सेवा से भी है, जिसका प्राविधान इस विनियम के अन्तर्गत समय-समय पर किया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

*[1]उपबन्ध यह है कि नगरपालिका, जिला परिषद, नगर सुधार प्रन्यास, छावनी बोर्ड अथवा नगर महापालिका में

(१) कार्य से भारित अधिष्ठान (वर्क चार्ज ऐस्टेब्लिशमेण्ट) की सेवा अवधि, तथा

(२) आकस्मिक निधि (कन्टिन्जेन्सी) से देय पारिश्रमिक वाले पद पर कार्य की सेवा अवधि, तथा

(३) पदच्युति (डिस्मिसल), निष्कासन (रिमूवल) तथा त्यागपत्र (रेजीनेशन) के फलस्वरूप व्याघातित (इन्टेरेप्टैड) सेवा के अतिरिक्त,

किसी एक पद अथवा अन्य पद पर स्थायी, अस्थाई अथवा स्थानापन्न सेवा भी अर्हकारी सेवा समझी जावेगी चाहे उसका भविष्य निधि काटा गया हो अथवा न काटा गया हो।

२(६) सेवा निवृत्ति से तात्पर्य किसी अधिकारी का महापालिका की सेवा से सेवा अवधि पूर्ण करने पर,*[2] स्थाई रूप से पूर्णतया अशक्त हो जाने पर, बाध्य किये जाने पर स्वेच्छा से अथवा स्थाई नियुक्ति वाले स्थाई पद के टूटने पर उसकी नियुक्ति दूसरे स्थाई पद पर न हो सकने अथवा उसके पूर्व स्थाई पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित न हो सकने की दशा में सेवा निवृत्ति होने से होगा।

---

*[1]यह संशोधन सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि १५-११-७५ से निर्णीत होने वाले मामलों पर लागू है। इससे पहले नियम २(८) का उपबन्ध निम्न प्रकार था :—

उपबन्ध यह है कि नगरपालिका, जिला बोर्ड, नगर सुधार प्रन्यास अथवा महापालिका में :—

(१) कार्य प्रभारित अधिष्ठान (वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमैन्ट) की सेवा अवधि

(२) आकस्मिक निधि (कन्टिन्जैन्सी) से देय पारिश्रमिक वाले पद पर कार्य की सेवा अवधि के अतिरिक्त किसी एक पद अथवा अन्य पद पर बिना व्याघात के सतत अस्थाई अथवा स्थानापन्न सेवा अर्हकारी सेवा समझी जायगी।

इसके पश्चात शासकीय गजट में १६ अप्रैल १६७४ को प्रकाशित होने पर उपबन्ध के अन्त में निम्न वाक्य खण्ड जोड़ा गया था :—

"चाहे उसका भविष्य निधि काटा गया हो अथवा न काटा गया हो।"

*[2]यह संशोधन सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि दिनांक १६ अप्रैल १६७४ से निर्णीत होने वाले मामलों पर प्रभावी है। इससे पहले :—

"सेवा अवधि पूर्ण करने पर" के बाद तथा "बाध्य किये जाने" से पूर्व वाक्य खण्ड 'स्थायी रूप से पूर्णतया अशक्त हो जाने पर" वाक्य खण्ड सम्मिलित करते हुए उपरोक्त स्पष्टीकरण भी जोड़ा गया था।

स्पष्टीकरण :–

विनियम २(६) में निहित 'स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति' का तात्पर्य है कि ५० वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अथवा २५ वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेने पर कोई अधिकारी, कर्मचारी या सेवक स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति हेतु प्रार्थना कर सकता है । प्रतिबन्ध यह है कि जिस तिथि से वह स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति चाहता है उसके तीन माह पूर्व उसे तदर्थ मुख्य नगर अधिकारी को नोटिस देना होगा तथा पूर्णतया अशक्त हो जाने पर किसी अधिकारी को मुख्य नगर अधिकारी द्वारा आवश्यक जाँच के पश्चात तीन माह का नोटिस देकर सेवा निवृत्त किया जा सकता है ।

प्रवर्तन

(३) यह नियम लागू होंगे :—

३(१) (१) उन सभी अधिकारियों पर जिनकी नियुक्ति इन विनियमों के प्रभावी होने के बाद महापालिका द्वारा अधिनियम की धारा १०६ के अन्तर्गत स्थायी रूप से सृजित किये गये सेवा निवृत्तीय पदों पर स्थायी रूप से हो तथा,

(२)(क) उन सभी अधिकारियों पर जो इन विनियमों के प्रभावी होने के दिनांक को एक्ट की धारा १०६ के अन्तर्गत सृजित ऐसे सेवा निवृत्तीय पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त हों,

२(ख) उन सभी अधिकारियों पर भी जो अधिनियम की धारा ५७७ (ङ) के अनुसार नियत दिन से इन विनियमों के प्रभावी होने तक अस्थायी रूप से महापालिका के पदाधिकारी और कर्मचारी रहे हों और जो सेवा निवृत्तीय पदों पर नियुक्त हों, तथा इन विनियमों के प्रभावी होने के पूर्व वाले दिन तक भविष्य निधि में अपना अंशदान (सब्सक्रिप्शन) जमा करते रहे हों, यदि वे इन विनियमों के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के तीन महीनों के अन्दर स्वेच्छा से इन विनियमों को इस शर्त के साथ अँगीकार करें कि उनकी भविष्य निधि में महापालिका, नगरपालिका अथवा नगर सुधार प्रन्यास द्वारा जमा किया गया अंशदान, जिसमें नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार गणनाकर बोनस तथा उस पर जमा किया गया ब्याज का अंश सन्निहित होगा, महापालिका द्वारा खोली गई सेवा निवृत्ति वेतन निधि में जमा कर दिया जायगा । अधिकारी द्वारा भविष्य निधि में जमा किया गया उसका अंशदान महापालिका द्वारा अलग खोले गये सामान्य भविष्य निधि खाते(जनरल प्रोविडेन्ट फण्ड) में जमा कर दिया जायगा ।

*प्रतिबन्ध यह है कि विनियम संख्या ३(२)(ख) में वर्णित ३ माह की अवधि को मुख्य नगर अधिकारी किसी भी विशेष परिस्थिति में हटा सकते हैं ।

---

*यह प्रतिबन्ध सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि ३० मार्च १९६७ से बढ़ाया गया है ।

Scanned with OKEN Scanner

स्पष्टीकरण :---

इन विनियमों को अंगीकार करने वाले अधिकारी के भविष्य निधि के खाते में बोनस व उस पर ब्याज को निकाल कर जमा धन, उसके ऊपर बकाये अग्रिम तथा उसके बीमा की किश्तों में दिये गये रुपये को मिलाकर होने वाली धनराशि का एक तिहाई भाग महापालिका, नगरपालिका तथा नगर सुधार प्रन्यास का अंशदान समझा जायगा। यदि किसी अधिकारी को इस वितरण में आपत्ति हो तो वह इन विनियमों के अंगीकार करने वाले प्रार्थना पत्र के साथ अपनी आपत्ति मुख्य नगर अधिकारी को भेज सकता है जो अन्तिम रूप से महापालिका का अंशदान निश्चय और निर्धारित करेंगे।

४(३) एक बार अंगीकृत विकल्प अन्तिम होगा।

४ भाग १ (डैथकम रिटायरमैन्ट ग्रेच्युटी) मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपादान

४(१) जिन अधिकारियों पर यह विनियम लागू होंगे उनको सेवा निवृत्ति पर अतिरिक्त उपादान (ग्रेच्युटी) भी दिया जायगा, जो इनकी मासिक उपलब्धियों के १५ गुने से अधिक न होकर वह धन होगा, जो उनकी मासिक उपलब्धि के १/३ को उनके द्वारा की गई अर्हकारी सेवा के पूर्ण अर्द्ध वार्षिक काल की संख्या को गुणा करने से प्राप्त होगा।

४(२) यदि किसी अधिकारी की सेवा काल में ही मृत्यु हो जाय तो उसके द्वारा मनोनीति किये हुये व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को जिन्हें उपदान प्राप्त करने का अधिकार विनियम संख्या ५ के उप नियम १ से ८ तक के अनुसार दिया गया हो, उपादान दिया जावेगा, जिसकी धनराशि उसके वेतन के १२ गुने से कम और १५ गुने से अधिक न होते हुये वह धनराशि होगी, जो उसकी मासिक उपलब्धि के १/४ को उसके द्वारा की गई अर्हकारी सेवा में पूर्ण अर्द्ध वार्षिक काल की संख्या में गुणा करने पर प्राप्त हो और यदि कोई व्यक्ति मनोनीति न किया गया हो तो उसी विनियम के उप नियम ९ में विहित रीति के अनुसार उपादान का भुगतान किया जायगा।

४(३) उप विनियम (१) और (२) के अन्तर्गत मिलने वाले उपादान की धनराशि किसी भी दशा में रु० २४,०००।- (चौबीस हजार रुपया) से अधिक न होगी।

४(४) यदि इन विनियमों के अन्तर्गत आने वाला कोई अधिकारी, जो सिविल सर्विस रेगुलेशन के अन्तर्नियम ४७४ या ४७५ए के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति वेतन और उपादान (ग्रेच्युटी) का अधिकारी हो गया हो अथवा उन्हें प्राप्त कर चुका हो और अनिवार्य सेवा निवृत्ति (कम्पलसरी रिटायरमैन्ट) के दिनांक के

५ वर्ष की कालावधि के अन्दर उसकी मृत्यु हो जाय और मृत्यु के दिनांक तक उपादान अथवा निवृत्ति वेतन, जिसमें उप विनियम (१) के अन्तर्गत दिया गया उपादान (ग्रेच्युटी) तथा सेवा निवृत्त वेतन का वह भाग जो उसके द्वारा संराशित कर लिया गया हो को सम्मिलित करके उसे प्राप्त कुल धनराशि उसके मासिक उपलब्धि के १२ गुने से कम हो तो जितनी कमी हो वह उप विनियम (२) में वर्णित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को अतिरिक्त उपादान (ग्रेच्युटी) के रूप में दी जायगी।

५--नामांकन :—

५(१) प्रत्येक महापालिका कर्मचारी, जिस पर यह विनियम लागू हों, ज्यों ही वह किसी स्थायी सेवा निवृत्ति वेतनीय पद पर ग्रहणाधिकार (लियन) प्राप्त करे, एक अथवा अधिक व्यक्तियों को उपादान (ग्रेच्युटी) जिसे विनियम (४) के उप विनियम (२) से (४) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाय अथवा वह उपादान जो उसे विनियम ८ के उप विनियम (१) के अन्तर्गत प्राप्त हों और उसे उसकी मृत्यु के पूर्व न दिया गया हो, प्राप्त करने के लिये नामांकित करेगा :—

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन करते समय अधिकारी का परिवार हो तो नामांकन परिवार के एक अथवा अधिक व्यक्तियों को छोड़कर अन्य किसी के प्रति न किया जायेगा।

टिप्पणी :—

साधारणतया नामांकन अथवा उसमें कोई परिवर्तन किसी अधिकारी द्वारा अपने सेवा काल में ही किया जा सकता है, किन्तु यदि आवश्यक हो तो सेवा निवृत्ति के बाद भी मुख्य नगर अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से पूर्व नामांकन पत्र के नामांकन में परिवर्तन अथवा नया नामांकन प्रस्तुत करने दिया जा सकता है।

५(२) यदि कोई अधिकारी ऊपर के उप विनियम के अन्तर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है तो उसे नामांकन पत्र में प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली धनराशि अथवा भाग को इस प्रकार स्पष्ट करना होगा जिससे उपादान (ग्रेच्युटी) का पूरा धन वितरित हो जाय।

५(३) अधिकारी नामांकन पत्र में निम्नांकित व्यवस्था कर सकेगा।

(क) किसी निर्दिष्ट नामांकित व्यक्ति की अधिकारी की मृत्यु के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उस नामांकित व्यक्ति का अधिकार नामांकन पत्र में दिये हुये किसी अन्य निर्दिष्ट व्यक्ति को हो जावे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन करते समय अधिकारी के परिवार में एक से अधिक व्यक्ति हों तो उक्त निर्दिष्ट व्यक्ति अधिकारी के परिवार के किसी सदस्य के अतिरिक्त अन्य न होगा।

(ख) नामांकन पत्र में उल्लिखित किसी प्रासंगिक परिस्थिति के उत्पन्न होने पर नामांकन निरर्थक हो जावेगा।

५(४) किसी अधिकारी द्वारा उस समय का किया हुआ नामांकन जब उसके परिवार नहीं था अथवा नामांकन में उप विनियम (३) के खण्ड (क) के अन्तर्गत की हुई व्यवस्था जब उसके परिवार में केवल एक ही व्यक्ति था, जैसी भी दशा हो, उस समय निरर्थक हो जायेगी, जब उसके परिवार हो जाय अथवा परिवार में कोई अतिरिक्त सदस्य हो जाय।

५(५) (क) प्रत्येक नामांकन (क) से (घ) तक के किसी प्रपत्र में जो भी व्यक्ति विशेष की स्थिति में उचित हो, किया जावेगा।

५(५) (ख) कोई अधिकारी किसी समय किसी नामांकन को मुख्य नगर अधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर रद्द कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अधिकारी उस नोटिस के साथ एक नामांकन पत्र इन विनियमों के अनुसार भेजे।

५(६) किसी नामांकित व्यक्ति, जिसके अधिकार को उसकी मृत्यु के पश्चात दूसरे नामांकित व्यक्ति को पाने की व्यवस्था नामांकन पत्र में उप विनियम (३) के खण्ड (क) के अन्तर्गत न की गई हो अथवा किसी ऐसी घटना के हो जाने पर जिसके कारण उसका नामाँकन उप विनियम (३) के खण्ड (ख) अथवा उप विनियम (४) के अन्तर्गत निरर्थक हो जाता हो तो सम्बन्धित अधिकारी मुख्य नगर अधिकारी को पूर्व नामांकन को रद्द करते हुये इन विनियमों के अनुसार नये नामांकन पत्र के साथ लिखित नोटिस भेजेगा।

५(७) प्रत्येक अधिकारी द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत भरे गये अपने नामांकन पत्र अथवा उस को रद्द करने का नोटिस सम्बधित अधिकारी द्वारा मुख्य नगर अधिकारी अथवा उसके द्वारा तदर्थ मनोनीत किये गये अधिकारी को भेजा जाना चाहिये। मुख्य नगर अधिकारी अथवा उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी नामांकन पत्र प्राप्त करने पर तुरन्त प्राप्ति का दिनांक लिखकर उसे प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे और अपने संरक्षण में रखेंगे।

५(८) किसी अधिकारी द्वारा किया गया पूर्व नामांकन अथवा उसके रद्द किये जाने का नोटिस जहां तक वह वैध (वैलिड) हो मुख्य नगर अधिकारी अथवा उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये दिनांक से प्रभावी होगा।

५(९) यदि किसी अधिकारी को, जिसके परिवार हो, परिवार के एक सदस्य अथवा अधिक सदस्यों की मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपादान पाने का नामांकन पत्र द्वारा अधिकार दिये बिना मृत्यु हो जाय तो उपादान विनियम (२) के उप नियम (४) में दी हुई श्रेणी के क्रम (क) से (घ) तक में दिये गये विधवा पुत्रियों को छोड़कर सभी जीवित सदस्यों को समान भागों में वितरित कर दिया जावेगा। यदि इस प्रकार के जीवित सदस्य न हों और एक अथवा अधिक विधवा पुत्रियाँ हो, तथा/अथवा अधिकारी के परिवार में उपरोक्त विनियम के क्रम (ङ) से (झ) तक में वर्णित कोई एक या उससे अधिक सदस्य हो तो उपादान की धनराशि उन सभी व्यक्तियों में बराबर भागों में बांट दी जावेगी।

६--भाग २ पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन

*६(१) प्रत्येक अधिकारी जो सेवा निवृत्ति वेतन के योग्य पन्द्रह वर्षों की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवा निवृत्ति होने पर अथवा सेवा में रहते हुये मृत हो जाय तो उसके परिवार को नीचे के उप विनियम (२) में वर्णित धनराशि से अधिक न होते हुए पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन उसकी विधवा पत्नी को आजीवन या जब तक वह पुनर्विवाह न करे अथवा परिवार के अन्य किसी सदस्य को प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अन्तर्गत रहते हुए अधिक से अधिक दस वर्ष तक दिया जायगा।

प्रतिबन्ध यह है कि पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन भुगतान की अवधि विधवा पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी दशा में मृत्यु यदि सेवा निवृत्ति होने के बाद हो तो उस दिनांक से जब सम्बन्धित अधिकारी सेवा अवधि पूर्ण होने पर सेवा निवृत्त हुआ हो या होता अथवा यदि मृत्यु सेवा में रहते हुए हो तो उस दिनांक से जब वह साधारण अवस्था में सेवा अवधि पूर्ण कर निवृत्ति वेतन प्राप्त कर सेवा निवृत्त होता, पांच वर्ष से अधिक न होगी।

टिप्पणी :—

(१) उस अधिकारी के सम्बन्ध में, जिसकी मृत्यु सवेतन सेवा निवृत्ति के लिए निवृत्ति पूर्व अवकाश काल में हो तो उसके सम्बन्ध में पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन के ५ वर्ष का समय उस दिनांक से गिना जायगा, जिस दिन साधारण अवस्था में वह निवृत्ति वेतन सहित सेवा निवृत्त होता तथा वह उस समय उस दिन से न गिना जायगा जिस दिनांक से वह अधिकारी सेवा निवृत्ति वेतन प्राप्त कर सेवा निवृत्ति होना चाहता था और दिनांक वास्तव में न आया।

---

*यह संशोधन सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि १९ अप्रैल १९७४ से निर्णीत होने वाले मामलों पर प्रभावी है। इससे पहले मूल नियम निम्न प्रकार था :—

प्रत्येक अधिकारी जो सेवा निवृत्ति वेतन के योग्य १५ वर्षों की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके चाहे सेवा निवृत्ति होने पर, सेवा निवृत्त होने की तिथि के ५ वर्ष के अन्दर अथवा सेवा में रहते हुए मृत हो जावे तो उसके परिवार को नीचे के उप विनियम (२) में वर्णित धनराशि से अधिक न होते हुए पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन १० वर्ष तक दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन भुगतान की अवधि किसी भी दशा में, मृत्यु यदि सेवा निवृत्ति के बाद हो तो उस दिनांक से जब सम्बन्धित अधिकारी सेवा अवधि पूर्ण होने पर सेवा निवृत्त हुआ हो या हुआ होता अथवा यदि मृत्यु सेवा में रहते हुए हो तो उस दिनांक से जब वह साधारण अवस्था में सेवा अवधि पूर्ण कर निवृत्ति वेतन प्राप्त कर सेवा निवृत्ति होता, ५ वर्ष से अधिक न होगी।

Scanned with OKEN Scanner

(२) कार्य कारिणी समिति अपने स्व-बिवेक से अपवाद की परिस्थितियों में (एकसेप्सनल सरकमस्टन्सेज) में पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन किसी ऐसे अधिकारी के परिवार को दे सकती है जो १५ वर्ष का सेवा काल पूर्ण करने के पूर्व कम से कम १० वर्ष अर्हकारी सेवा पूर्ण करके मृत हो गया हो।

६(२) पारिवारिक निवृत्ति वेतन की धनराशि निम्न प्रकार निर्धारित की जावेगी :—

(क) सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की दशा में उस निवृत्ति वेतन का आधा जो सम्बन्धित अधिकारी को मृत्यु होने के अगले दिन देय होता, यदि वह उस दिन नियत सेवा अवधि पूर्ण होने पर सेवा निवृत्त कर दिया जाता।

(ख) सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु होने की दशा में उसको सेवा निवृत्ति पर स्वीकृत किये गये सेवा निवृत्ति वेतन (पेन्शन) का आधा।

प्रतिबन्ध यह है कि पारिवारिक निवृत्ति वेतन का धन अधिक से अधिक रु० १५०/- से अधिक न होगा, तथा कम से कम रु० ३०/- प्रतिमास से कम न होगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन (पेन्शन) की न्यूनतम धनराशि सम्बन्धित अधिकारी को उसकी सेवा निवृत्ति पर स्वीकृत होने वाले सेवा निवृत्ति वेतन (पेन्शन) की धनराशि से अधिक न होगी, अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाय तो सेवा निवृत्ति वेतन (पेन्शन) उस धनराशि से अधिक न होगी जो उसे मृत्यु के बाद वाले दिन सेवा निवृत्त होने पर निवृत्ति वेतन के रूप में प्राप्त होता।

टिप्पणी :—

यदि पेन्शन पाने वाले अधिकारी ने अपने पेन्शन के किसी अंश का संराशिकरण (कम्यूटेशन) करा लिया है तो पारिवारिक पेन्शन उस अंश के बराबर कम कर दी जायगी।

उदाहरणार्थ :—यदि पेन्शन रु० ९०/- प्रतिमास हो और इसमें से रु० ३०/- संराशिकरण करा लिया हो तो पारिवारिक पेन्शन ९०/२ ऋण ३० अर्थात रु० १५/- प्रतिमास होगी।

६(३) इस भाग के अन्तर्गत कोई पेन्शन देय न होगी।

(क) नीचे के उप नियम (४) के खण्ड (ख) में उल्लिखित किसी व्यक्ति की जब तक कि मुख्य नगर अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट न हों कि वह व्यक्ति जिसे पेन्शन दी जाने वाली है अपने पोषण के लिये मृत अधिकारी पर आश्रित था।

(ख) किसी अविवाहिता स्त्री सदस्या को उसके विवाहित होने की दशा में।

(ग) परिवार के किसी विधवा स्त्री सदस्या को यदि वह पुनः विवाह कर ले।

(घ) मृत अधिकारी के किसी भाई को उसके १८ वर्ष की अवस्था पूर्ण कर लेने पर। तथा

(ङ) किसी ऐसे व्यक्ति को जो मृत अधिकारी के परिवार का सदस्य न हो।

६(४) उप विनियम (५) के अन्तर्गत किये गये नामांकन पत्र में की गई व्यवस्था को छोड़ कर :—

(क) इस भाग के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया सेवा निवृत्ति वेतन (पेन्शन) निम्न प्रकार दिया जायगा :—

(१) उत्तर जीवी श्रेष्ठ विधवा को, यदि मृत पुरुष अधिकारी हो अथवा पति को यदि मृतक महिला अधिकारी हो।

(२) विधवा पत्नी अथवा पति, जैसी भी दशा हो, के न होने पर उत्तर जीवी श्रेष्ठ पुत्र को।

(३) उपर्युक्त नम्बर (१) व (२) की दशा के न होने पर उत्तर जीवी ज्येष्ठ अविवाहिता पुत्री को, तथा

(४) उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं के अभाव में विधवा ज्येष्ठ पुत्री को, तथा

६(४) (ख) खण्ड (क) के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति वेतन किसी व्यक्ति को देय न होने की दशा में वह निवृत्ति वेतन (पेन्शन) निम्न प्रकार स्वीकार की जावेगी।

(१) पिता को

(२) पिता के न होने पर माता को

(३) पिता और माता के न होने पर उत्तर जीवी भ्राताओं में उसको जिसकी अवस्था १८ वर्ष से कम हो।

(४) इन सबके न होने पर ज्येष्ठ उत्तर जीवी अविवाहित बहिन को, तथा

(५) उपर्युक्त नम्बर (१) से (४) में उल्लिखित के न होने पर ज्येष्ठ उत्तर जीवी विधवा बहिन तथा

(६) (१) से (५) तक वर्णित व्यक्तियों के न होने की दशा में पूर्व मृत पुत्र के बच्चों को उस क्रम में जिसमें मृत अधिकारी के बच्चों को ऊपर के खण्ड (क) के उप खण्ड (२) (३) और (४) के अन्तर्गत देय हो।

Scanned with OKEN Scanner

टिप्पणी :—

ऊपर के खण्ड (क) (१) के अन्तर्गत प्रयोग किये गये ज्येष्ठ उत्तर जीवी विधवा शब्दों की व्याख्या मृत अधिकारी के साथ हुए विवाह सम्बन्ध की पूर्वता क्रम से की जायगी न कि उत्तर जीवी विधवाओं की आयु के उल्लेख से ।

६(५) प्रत्येक महापालिका अधिकारी अपनी नियुक्ति के स्थायीकरण के तुरन्त बाद प्रपत्र (ड.) में यह दिखाते हुए कि इस भाग के अन्तर्गत स्वीकृत की गई पेन्न उसके परिवार के सदस्यों को किस प्रकार देय होगी, नामांकन पत्र दाखिल करेगा और जहां तक वह वध होगा पारिवारिक निवृत्ति वेतन इस प्रकार किये गये नामांकन के अनुसार दिया जावेगा । किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नामांकित व्यक्ति, जिस दिन से निवृत्ति वेतन देय हो, ऊपर के उप विनियम (३) के अन्तर्गत निवृत्ति वेतन प्राप्त करने के लिए अयोग्य न हो जाय । यदि नामांकित व्यक्ति उप विनियम के अन्तर्गत वेतन (पेन्शन) पाने अयोग्य हो गया हो अथवा हो जाय तो निवृत्ति वेतन नामांकन पत्र के दिये हुये क्रम के अनुसार उसके बाद वाले व्यक्ति को दिया जायगा । इस उप विनियम के अन्तर्गत किये गये नामांकनों के सम्बन्ध में नियम ५ के उप विनियम (५) (ख) (७) और (८) लागू होंगे ।

६(६)क इस भाग के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया सेवा निवृत्ति वेतन (पेन्शन) एक समय में मृत अधिकारी के परिवार के एक से अधिक सदस्य को देय न होगा ।

(ख) इस भाग के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया सेवा निवृत्ति वेतन (पेन्शन) यदि परिवार के किसी सदस्य को उप विनियम (१) के अन्तर्गत दिये हुए समय के अन्दर उसकी मृत्यु, हो जाने अथवा उसके विवाह कर लेने अथवा अन्य किसी कारण से देय रह जावे तो वह निवृत्ति वेतन (पेन्शन) उप विनियम (४) के अन्तर्गत दिये हुए उसके बाद वाले व्यक्ति (अधिकारी) को पुनः स्वीकृत किया जायगा अथवा उप विनियम (५) के अन्तर्गत किये गये नामांकन में उसके बाद वाले क्रम में आने वाले व्यक्ति को जैसी भी दशा हो और जो इस भाग के दूसरे नियमों की पूर्ति करता हो, दिया जावेगा ।

६(७) इस भाग में स्वीकृत किया गया सेवा निवृत्ति वेतन किसी असाधारण सेवा निवृत्ति (पेन्शन), उपादान अथवा कारुण्य अधिदेय, (कम्पनसेशन) जो तत्कालीन लागू नियमों और अधिनियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया हो, के अतिरिक्त देय होगा ।

६(८) इस भाग के अन्तर्गत स्वीकृत प्रत्येक सेवा निवृत्ति वेतन (पेन्शन) के लिये प्राप्तकर्ता के लिये अच्छे आचरण का होना आवश्यक प्रतिबन्ध (कन्डीशन) होगा । यदि किसी सेवा निवृत्ति वेतन (पेन्शन) प्राप्तकर्ता को किसी गम्भीर अपराध में सजा हो जाय अथवा घोर दुराचरण (ग्रेट-मिसकन्डक्ट) का अपराधी

पाया जाय तो कार्यकारिणी समिति को पूरी सेवा निवृत्ति वेतन (पेन्शन) अथवा उसके कुछ भाग को रोक देने का अधिकार होगा।

ऐसे विषयों में कार्यकारिणी समिति का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा। जब तक महापालिका उसमें कोई परिवर्तन न कर दें।

भाग ३--निवृत्ति वेतन

७ अधिवर्ष निवृत्ति, अशक्त या अन्य प्रकार से निवृत्ति वेतन या उपादान (सुपर ऐनुएशन रिटायरिंग इनवैलिड एण्ड अदर पेन्शन और ग्रेच्युटी) अनुबद्ध में लिखित समुचित धनराशि होगा।

*[1]पेन्शन की धनराशि पूरे रुपयों में अभिव्यक्त की जायेगी और जहाँ भी नियमानुसार गणना करने पर पेन्शन रुपये से कम कोई धनराशि हो तो वह अगले पूर्ण रुपये में बदल दी जायेगी।

८—विनियम ७ के अन्तर्गत देय निवृत्ति वेतन (पेन्शन) सम्बन्धित अधिकारी को उसकी मृत्यु के दिन तक दी जायगी,

प्रपत्र (ड.) में पारिवारिक निवृत्ति वेतन को पाने के लिये अधिकृत व्यक्ति को *[2]जीवन काल के कुल बकाया धन का भुगतान किया जावे।

भाग ४--संराशिकरण (कम्यूटेशन)

९—प्रत्येक अधिकारी जिसे इन विनियमों के विनियम ७ के अन्तर्गत निवृत्ति वेतन मिलता है, उसे उस विनियम के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले निवृत्ति वेतन की धनराशि का १/३ भाग तक किसी भाग के संराशिकरण (कम्यूटेशन) कराने का अधिकार होगा तथा इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सिविल पेन्शन कम्यूटेशन रूल्स इस *[3]प्रतिबन्ध के साथ लागू होंगे कि उक्त कम्यूटेशन रूल्स के नियम १८ के तात्पर्य के लिये प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, चिकित्सा परिषद का गठन करेंगे। जिसके लिए चिकित्सा अधिका-

---

*[1]उपरोक्त वाक्य सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि २ मार्च १९६८ से बढ़ाया गया।

*[2]प्रपत्र (ड.) की दूसरी लाइन में शब्द 'पारिवारिक निवृत्ति वेतन' के बाद निम्न और जोड़ा गया :-"और जीवन काल के कुल बकाया धन का भुगतान।"

प्रपत्र (ड.) में उपरोक्त संशोधन तथा विनियम ८ में व्यक्ति को तथा भुगतान के बीच वाक्यांश 'जीवन काल के कुल बकाया धन का भुगतान' को सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि ३० मार्च १९६७ से बढ़ाया गया है।

*[3]विनियम ९ में यह प्रतिबन्ध सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि (१५ नवम्बर १९७५) से निर्णीत होने वाले मामलों के लिये बढ़ाया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

रियों को नामोदिष्ट (नामीनेट) करेंगे तथा नियम २२ के अनुसार देय कुल शुल्क (टोटल फी) प्रार्थी द्वारा महापालिका निधि में जमा की जावेगी। जब तक कि प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी राज्य सरकार की स्वीकृति से शुल्क के किसी भाग को चिकित्सा परिषद के सदस्यों या चिकित्सा अधिकारी को देना न निश्चित करें।

प्रतिबन्ध यह है कि संराशिकरण के बाद देय सेवा निवृत्ति वेतन (पेन्शन) की धनराशि किसी भी दशा में सिविल सर्विस रेगुलेशन के अन्तर्नियम ४७४ तथा ४७४ए के अन्तर्गत निकलने वाले सेवा निवृत्ति वेतन (पेन्शन) के आधे अथवा बीस रुपया जो भी अधिक हो, से कम न होगा।

टिप्पणी :--

प्रशासक ने अपने आदेश दिनांक २१-२-७६ के अनुसार सिविल पेन्सिल कम्यूटेशन रूल्स के नियम १८ के तात्पर्य के लिए चिकित्सा परिषद का गठन तथा चिकित्साधिकारियों का नाम निर्देशन निम्न प्रकार किया है :--

१. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अध्यक्ष
२. अतिरिक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सदस्य
३. डा० ऐस० के० दास सरदार पटेल चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी सदस्य

भाग ५--विविध

१०(१) कार्य कारिणी समिति की स्वीकृति से उपादान अथवा स्वीकृत पारिवारिक निवृत्ति वेतन की धनराशि से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा महापालिका को नियमानुसार देय तथा वसूल की जा सकने योग्य धनराशि वसूल की जा सकती है।

(२) यदि कोई अधिकारी दुराचरण, जिसमें कैद की सजा हो जाय, दिवालिया होने या गबन करने के कारण बर्खास्त (डिसमिस) कर दिया गया हो, अथवा निकाल (रिमूव कर) दिया गया हो तो साधारणत : उसे अथवा उसके परिवार को कोई उपादान अथवा पारिवारिक पेन्शन देय न होगी। किन्तु कार्य कारिणी समिति यदि ऐसा निश्चय करे तो विनियम ४ के अन्तर्गत प्राप्त हो सकने वाले उपादान की धनराशि का आधा धन दया के आधार (कम्पेंशनेट ग्राउण्ड) पर दिया जा सकता है।

(११) इन विनियमों के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति वेतन के अधिकारी होने वाले प्रत्येक अधिकारी के लिये मुख्य नगर अधिकारी फाइनेन्शियल हैंड बुक २ के भाग २ से ४ के नियम संख्या ११६ के सम्बन्ध में गवर्नर महोदय के आदेश संख्या १ में दी हुई तालिका के अनुसार प्रत्येक मास निवृत्ति वेतन का अंशदान

Scanned with OKEN Scanner

उस निधि से, जिससे उसका वेतन देय हो, निकाल कर निवृत्ति वेतन निधि में जमा करेंगे। इस कार्य के लिये मुख्य नगर अधिकारी सभी कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय तथा अधीनस्थ सेवाओं में विभाजित करेंगे। इस निधि का धन महापालिका द्वारा निर्धारित बैंक में निवृत्ति वेतन निधि के नाम से हिसाब खोल कर प्रत्येक मास की ४ तारीख के पूर्व जमा किया जायगा। भुगतान की सुविधा के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया बैंक में भी करैन्ट एकाउन्ट रखा जा सकता है, यदि किसी समय उपरोक्त खातों में सेवा निवृत्ति वेतन अथवा उपादान के भुगतान के लिये आवश्यकतानुसार धन न हो तो मुख्य नगर अधिकारी महापालिका निधि से आवश्यक अग्रिम धन की व्यवस्था करेंगे और बाद में उसे निवृत्ति वेतन निधि से निकालकर महापालिका निधि में जमा कर देंगे। मुख्य नगर अधिकारी बैंक में जमा किये हुए धन को कार्य कारिणी समिति की स्वीकृति से सरकारी पत्रों में विनियोजित कर सकेंगे। किन्तु एक मास में भुगतान होने वाले धन के बराबर का धन सदैव बैंक अथवा स्टेट बैंक में रखेंगे।

निवृत्ति वेतन और उपादान के स्वीकृति की विधि

१२(१) प्रत्येक अधिकारी के सेवा निवृत्ति होने के बाद और प्रत्येक दशा में उसके एक महीने के अन्दर उसके विभागीय अधिकारी उसकी सेवा पुस्तिका तथा सम्बन्धित अन्य विवरणों को प्रपत्र (च) के साथ पूरा करके लेखा अधिकारी को भेजेंगे। लेखा अधिकारी सेवा निवृत्ति वेतन की धनराशि तथा अन्य विवरणों की जांच करके मुख्य नगर लेखा परीक्षक को जांच के लिये सम्बन्धित कागज भेजेंगे। उनकी जांच के बाद उपादान तथा सेवा निवृत्ति वेतन तथा उपादान की धनराशि मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के विषय में स्वीकृत किया जावेगा तथा लेखा अधिकारी द्वारा सेवा निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका प्रपत्र 'छ' सम्बन्धित अधिकारी को भेजा जायेगा।

*१"प्रतिबन्ध यह रहेगा कि सेवा निवृत्ति के बाद उपादान की सम्भावित धनराशि का एवं सेवा निवृत्ति वेतन की सम्भावित धनराशि का २/३ (दो तिहाई) भाग लेखा अधिकारी की जाँच के पश्चात् परन्तु मुख्य नगर लेखा परीक्षक की जाँच के पूर्व भी अग्रिम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जिसको उपादान एवं सेवा निवृत्ति वेतन के अन्तिम रूप से निर्धारण होने पर कुल देय धनराशि में से काट कर समायोजित कर लिया जायगा।" *२"किन्तु उपादान एवं सेवा निवृत्ति वेतन की सम्भावित धनराशि के दो तिहाई भाग के भुगतान से पूर्व सम्बन्धित कर्मचारी को निम्नांकित प्रपत्र में एक घोषणा पत्र देना होगा।"

---

*१ यह संशोधन सरकारी गजट में प्रकाशन की दिनांक १९ अप्रैल १९७५ से निर्णीत होने वाले मामलों पर प्रभावी है।

*२ यह संशोधन सरकारी गजट में प्रकाशन की दिनांक १५ नवम्बर १९७५ से निर्णीत होने वाले मामलों पर प्रभावी है।

Scanned with OKEN Scanner

घोषणा पत्र का प्रारूप

चूंकि प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, आगरा मुझे देय सेवा निवृत्ति वेतन उपादान तथा सेवा निवृत्ति वेतन का सही धन निर्धारित किये जाने और उसकी आवश्यक जाँच की पूर्ति की प्रत्याशा में सेवा निवृत्ति वेतन उपादान की सम्भावित धनराशि में से रु० ..... शब्देन (..... रु० मात्र) और सेवा निवृत्ति वेतन की सम्भावित धनराशि में से रु० ..... शब्देन (..... रुपया मात्र) अग्रिम रूप में अन्तःकालीन भुगतान करने के लिये सहमत हो गये हैं। अतः मैं इस लेख द्वारा स्वीकार करता हूँ कि उपादान और सेवा निवृत्ति वेतन के मासिक अग्रिम (एडवान्स) के ग्रहण करने में मैं पूरी तरह यह समझता हूँ कि यह मुझे देय सेवा निवृत्त उपादान और सेवा निवृत्ति वेतन की आवश्यक यथाविधि जाँच पूरी होने पर संशोधनीय है और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस संशोधन में मैं इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं करूंगा कि प्रत्याशित सेवा निवृत्ति उपादान या मासिक सेवा निवृत्ति वेतन जो इस समय मुझे भुगतान किया जा रहा है, उस सेवा निवृत्ति उपादान या/और मासिक सेवा निवृत्ति वेतन से अधिक है जो अन्तिम रूप से मुझे स्वीकार किया जावेगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि सेवा निवृत्ति उपादान और मासिक सेवा निवृत्ति वेतन का जो धन अन्तिम रूप से स्वीकार किया जावे, उससे अधिक जो भी भुगतान मुझे होगा मैं तुरन्त लौटा दूँगा।

साक्षी—

१— नाम — हस्ताक्षर
पता — दिनांक
पता
२— नाम — स्टेशन
पता

नोट :—अनावश्यक शब्द काट दीजिए।

सेवा निवृत्ति वेतन व उपादान के भुगतान की विधि

१२(२) सेवा निवृत्ति वेतन लेखा अधिकारी द्वारा भुगतान किया जावेगा, *रु० १५०/- तक के भुगतान नकद अन्यथा चैक द्वारा किये जायेंगे, नकद भुगतान के लिये सेवा निवृत्ति वेतन पाने वाले व्यक्तियों को अपनी सेवा निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पुस्तिका तथा प्रपत्र (ज) में आवश्यक विवरण भर कर लेखा अधिकारी को देना होगा। प्रपत्र 'ज' व निवृत्ति वेतन आदेश पाने पर लेखा अधिकारी तदर्थ बैंक से निकाले हुए धन से उनको भुगतान करेंगे। जिन्हें भुगतान चैक से होता है, उन्हें प्रपत्र (ज) के साथ निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश

*दिनांक ८-४-६७ को शासकीय गजट में प्रकाशित संशोधन के अनुसार रु० ५०/- के स्थान पर-रु० १५०/- किये गये हैं।

पाने पर लेखा अधिकारी चैक द्वारा उनको भुगतान करेंगे। इन विनियमों के अन्तर्गत भुगतान होने वाले उपादान के भुगतान में भी निवृत्ति वेतन के भुगतान की रीति काम में लाई जायेगी।

*निम्न दशाओं के अतिरिक्त प्रत्येक पेन्शनर को प्रपत्र 'ज' में जीवित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु लेखाधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना आवश्यक है :—

(क) उन व्यक्तियों को जो बीमारी अथवा शारीरिक अशक्ति के कारण स्वयम् उपस्थित होने में असमर्थ हों, वे यदि प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी से आदेश प्राप्त करलें तो किसी वरिष्ठ महापालिका अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति जिसे इस प्रयोजन हेतु प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी प्राधिकृत कर दें, के द्वारा सम्बन्धित पेन्शनर के जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पेंन्शनर की स्वयम् की पावती पर उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को भुगतान किया जावेगा।

(ख) उन व्यक्तियों को जो आगरा से बाहर हों, किसी राजपत्रित अधिकारी/संसद सदस्य/विधायक से जीवित होने का प्रमाण पत्र सहित प्रार्थना पत्र स्पष्ट विकल्प के साथ कि धनराशि क्रास्ड चैक/क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट/धनादेश (मनी आर्डर) में से किस माध्यम से भेजी जाय, प्राप्त होने पर पेन्शनर की स्वयम् की जिम्मेदारी पर क्रास्ड चैक/क्रास्ड ड्राफ्ट/धनादेश द्वारा भेजने में जो भी व्यय हो, उसे पेन्शनर को देय धनराशि में से काट कर शेष धनराशि उसके पास भेज दी जावेगी। इस प्रकार भुगतान होने में किसी भी गलत हस्तान्तरण के लिये महापालिका का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(ग) ऊपर की (क) तथा (ख) प्रत्येक दशा में पेन्शनर को वर्ष में कम से कम एक बार उपरोक्त जीवन सम्बन्धी प्रमाण पत्र के अतिरिक्त जीवित होने के सबूत के रूप में लेखा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना आवश्यक होगा।

उपरोक्त शर्तों के अनुसार प्रपत्र 'छ' की टिप्पणी नं० १ में भी संशोधन कर दिया है, संशोधित प्रपत्र 'छ' संलग्न है।

सामान्य भविष्य निधि

१३—जिन अधिकारियों को ये विनियम प्रभावी होंगे, उन्हें महापालिका की सामान्य भविष्य निधि का सदस्य होना पड़ेगा तथा उसमें अपने मासिक वेतन से १२ पैसा प्रति रुपया से कम न होते हुए २० पैसे प्रति रुपया तक अपना अंशदान प्रतिमास जमा करना पड़ेगा। अंशदान की दर उन्हें अपनी नियुक्ति

---

* यह संशोधन शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि दिनांक (१५ नवम्बर १९७५) से प्रभावी है।

के बाद बाद घोषित कर देनी पड़ेगी. *जब तक कि वे इसमें किसी परिवर्तन का प्रार्थना पत्र मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षक जैसी भी स्थिति हो, को किसी वर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह में न दें अगले वर्ष के लिये वही दर बनी रहेगी तथा वर्ष के बीच में दर में कोई परिवर्तन स्वीकृत न किया जायगा।

मुख्य नगर अधिकारी प्रत्येक अधिकारी का अंशदान उसके मासिक वेतन बिल से काटकर सामान्य भविष्य निधि के खाता में बैंक में हिसाब खोलकर उस में जमा करेंगे तथा प्रत्येक सदस्य का खाता प्रपत्र संख्या 'झ' में रखेंगे।

१४—भविष्य निधि के अंशदान में काटा गया धन प्रतिमास की ४ तारीख से पहले बैंक में जमा कर दिया जावेगा जिससे उसमें ब्याज मिल सके।

१५—मुख्य नगर अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अभिदाताओं के हित में कार्य कारिणी समिति की स्वीकृति से सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धन में से धन निकाले तथा उसे सरकारी ऋण पत्रों में विनियोजित कर दे।

१६—प्रत्येक आर्थिक वर्ष के अन्त में मुख्य नगर अधिकारी बैंक तथा विनियम १५ के अन्तर्गत विनियोजनों से प्राप्त ब्याज का हिसाब बना देंगे। तब वे कुल जमा धन तथा वर्ष में मिले ब्याज के आधार पर प्रत्येक सदस्य के हिसाब में जमा होने वाले ब्याज की दर निश्चित करेंगे। इसके बाद एक ब्याज सारिणी (ब्राड शीट) प्रपत्र 'ट' में बनाया जायगा तथा प्रत्येक खाते में ब्याज लग जाने पर मुख्य नगर अधिकारी प्रपत्र 'ठ' में पिछले वर्ष के हिसाब का विवरण सम्बन्धित सदस्यों को सूचनार्थ भेजेंगे। हिसाब प्राप्त होने पर सम्बन्धित सदस्यों को यह अधिकार होगा कि वे अपने खाते का हिसाब देख सकते हैं, और यदि उसमें कोई अपने हिसाब में त्रुटि पावें तो वह आवश्यकतानुसार मुख्य नगर अधिकारी से सुधार करा सकता है। यदि ब्याज का कुछ धन अवितरित रह जाय तो वह अगले वर्ष बंटने के लिये हिसाब में जोड़ दिया जायगा।

१७—प्रत्येक अधिकारी को भविष्य निधि का सदस्य होने पर उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके खाते में जमा भविष्य निधि के धन को भुगतान करने के लिये नामांकन पत्र विनियम ५ के अनुसार देना होगा। यह नामांकन पत्र मुख्य नगर अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायेंगे और प्राप्ति का दिनांक लिख कर तथा आवश्यक रजिस्टर में दर्ज करके अपने तत्त्वावधान (कस्टडी) में रखे जायेंगे।

१८—सामान्य भविष्य निधि में जमा हुए धन में से यदि कोई अधिकारी चाहे तो मुख्य नगर अधिकारी उसे अस्थायी ऋण स्वीकृत कर सकते हैं। इन ऋणों को तथा उनकी वसूली के लिये निम्नांकित विधि अपनाई जायेगी :—

---

* यह संशोधन शासकीय गजट दिनांक १५-११-७५ के अनुसार विनियम १३ के प्रथम अनुच्छेद में किया गया।

(१) साधारणतया ऋण की धनराशि सम्बन्धित अधिकारी के ३ मास के वेतन अथवा उसकी निधि के आधे से जो भी कम हो, अधिक न होगी। विशेष परिस्थिति में मुख्य नगर अधिकारी अपने स्व-विवेक से अधिक धन भी दे सकते है, जो सम्बन्धित अधिकारी के एक वर्ष के वेतन अथवा उसकी निधि के आधे मे जो भी कम हो अधिक न होगा।

(२) यह ऋण अधिकारियों को प्रायः ऐसे व्ययों को वहन करने के लिये दिये जायेंगे, जिनका वहन करना उनके धार्मिक अथवा सामाजिक बन्धनों के अन्तर्गत अनिवार्य हो, इन व्ययों में अधिकारी के अपने अथवा अपने परिवार के सदस्यों की शिक्षा, बीमारी, विवाह अथवा अपने परिवार के अन्य इस प्रकार के व्यय सम्मिलित समझे जायेंगे।

(३) यह ऋण अधिकारी से २४ से लेकर २८ किस्तों तक में वसूल किये जायेंगे। इन ऋणों पर ब्याज ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष लगेगा। ऋण की पूरी धनराशि अदा हो जाने पर ब्याज ऐसी आसान किस्तों में वसूल किया जायगा जिनकी धनराशि मूलधन की देय किस्तों से कम न हो। मूल धन तथा ब्याज की किस्तें वसूल होने पर सम्बन्धित कर्मचारी के खाते में जमा कर दी जायेगी।

(४) ऋण ब्याज सहित पूरा होने के १२ महीने के बाद दूसरा ऋण दिया जायगा। यदि पूर्वतर ऋण स्वीकृति की आवश्यकता न हो जाय।

१६—यदि कोई अधिकारी चाहे तो अपने सामान्य भविष्य निधि में जमा धन से अपनी जीवन बीमा पालिसी का प्रव्याज (प्रीमियम) अदा करने के लिये पालिसी को मुख्य नगर अधिकारी के नाम प्रतिग्रहण (प्लेज) करके अग्रिम ले सकता है। इस प्रकार प्रतिग्रहण (प्लेज) की हुई पालिसी मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के संरक्षण (कस्टडी) में रहेगी। पालिसी के प्रव्याज (प्रीमियम) के निमित्त लिये गये अग्रिम धन को बीमा कारपोरेशन को भुगतान किये जाने के सबूत में कारपोरेशन की रसीद मुख्य नगर अधिकारी के पास जमा करनी होगी। इस प्रकार की पालिसी को चालू रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी। पालिसी परिपक्व (मिच्योर) होने पर उसका रुपया वसूल करके अधिकारी के खाते में भविष्य निधि में जमा कर दिया जायगा। यदि सम्बन्धित अधिकारी पालिसी परिपक्व होने के पूर्व सेवा निवृत्त हो जाय तो मुख्य नगर अधिकारी उक्त अधिकारी के हित में पालिसी प्रतिग्रहण करके उसे लौटा देंगे।

*२०—किसी अधिकारी के खाते में सामान्य भविष्य निधि में जमा धन उसके महापालिका की सेवा से निवृत्ति होने पर उसे लौटा दिया जायगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी/कर्मचारी चाहे तो सामान्य भविष्य निधि में अपने खाते में साधारणतः जमा धन के आधे से अनधिक धन को या उसके ६ माह के वेतन तक इसमें जो भी कम हो, २३ वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अथवा सेवा अवधि पूर्ण होने से १० वर्ष पूर्व अपने निवास के लिए मकान बनाने, क्रय करने, मरम्मत करने या इस सम्बन्ध में लिये गये ऋण को अदा करने अथवा अपनी लड़की या लड़के के विवाह करने व अपने आश्रित बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने हेतु एवं मोटर कार क्रय करने या उक्त प्रयोजन से पहले ही लिये गये ऋण को प्रतिदान करने हेतु मुख्य नगर अधिकारी/प्रशासक की स्वीकृति से अन्तिम निष्कासन ले सकता है। विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत करने वाले अधिकारी को यह क्षमता होगी कि वह सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधिका ३/४ भाग तक के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति प्रदान कर दें।

उपरोक्त धन निकालने के ६ माह के भीतर मुख्य नगर अधिकारी को सन्तोष दिलाना होगा कि धन उस कार्य में, जिसके लिये वह निकाला गया था, प्रयोग कर लिया गया है। ऐसा न करने पर अग्रिम लिया धन मुख्य नगर अधिकारी को सामान्य भविष्य निधि में उसके खाते में जमा करने के लिये लौटा देना होगा। यदि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी मुख्य नगर अधिकारी को व्यय के विषय में सन्तोष न दिला सके अथवा बचा हुआ धन न लौटाये तो मुख्य नगर अधिकारी वह धन उसके वेतन से उचित किस्तों में वसूल कर लेने के लिये सक्षम होंगे।

---

* यह संशोधन उत्तर प्रदेश शासन के राज पत्र (शासकीय गजट) में प्रकाशन की तिथि (१५ नवम्बर १९७५) से प्रभावी है। इससे पहले नियम २० निम्न प्रकार था :—

२०—किसी अधिकारी के खाते में सामान्य भविष्य निधि में जमा धन उसके महापालिका की सेवा से निवृत्ति होने पर उसे लौटा दिया जायगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी चाहे तो सामान्य भविष्य निधि में अपने खाते में जमा धन के आधे से अनधिक धन को २३ वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अथवा सेवा अवधि पूर्ण होने से १० वर्ष पूर्व अपने निवास के लिये मकान बनाने या उस सम्बन्ध में लिये गये ऋण को अदा करने के लिये निकाल सकता है। दोनों ही दशाओं में धन निकालने के छः माह के भीतर मुख्य नगर अधिकारी को सन्तोष दिलाना होगा कि धन उस कार्य में जिसके लिये निकाला गया था प्रयोग कर लिया गया है। ऐसा न करने पर अग्रिम लिया गया धन मुख्य नगर अधिकारी को सामान्य भविष्य निधि में उसके खाते में जमा करने के लिये लौटा देना होगा, यदि सम्बन्धित अधिकारी मुख्य नगर अधिकारी को व्यय के विषय में सन्तोष न दिला सके अथवा बचा हुआ धन न लौटावे तो मुख्य नगर अधिकारी वह धन उसके वेतन से उचित किस्तों में वसूल करने के लिए सक्षम होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

अनुबन्ध

अहँकारी सेवा की पूर्ण छमाही	उपादान या निवृत्त-वेतन सारिणी	वार्षिक निवृत्त-वेतन की अधिकतम धनराशि (रुपयों में)
१	२	३
	(क) उपादान	
१—	१/२ मासिक उपलब्धि	
२—	१ ,,	
३—	१ १/२ ,,	
४—	२ ,,	
५—	२ १/२ ,,	
६—	३ ,,	
७—	३ १/२ ,,	
८—	४ ,,	
९—	४ १/२ ,,	
१०—	५ ,,	
११—	५ १/२ ,,	
१२—	६ ,,	
१३—	६ १/२ ,,	
१४—	७ ,,	
१५—	७ १/२ ,,	
१६—	८ ,,	
१७—	८ १/२ ,,	
१८—	९ ,,	
१९—	९ १/२ ,,	
	(ख) निवृत्त वेतन	
२०—औसत उपलब्धि का	१०/६०	३,०००
२१— ,,	१० १/२ बटे ६०	३,१५०
२२— ,,	११/६०	३,३००
२३— ,,	११ १/२ बटे ६०	३,४५०
२४— ,,	१२/६०	३,६००
२५— ,,	१२ १/२ बटे ६०	३,७५०
२६— ,,	१३/६०	३,९००
२७— ,,	१३ १/२ बटे ६०	४,०५०
२८— ,,	१४/६०	४,२००
२९— ,,	१४ १/२ बटे ६०	४,३५०
३०— ,,	१५/६०	४,५००

अर्हकारी सेवा की पूर्ण छमाही	उपादान या निवृत्त-वेतन सारिणी	वार्षिक निवृत्त-वेतन की अधिकतम धनराशि (रुपयों में)
१	२	३
३१—औसत उपलब्धि का	१५ १/२ बटे ६०	४,६५०
३२— ,,	१६/६०	४,८००
३३— ,,	१६ १/२ बटे ६०	४,९५०
३४— ,,	१७/६०	५,१००
३५— ,,	१७ १/२ बटे ६०	५,२५०
३६— ,,	१८/६०	५,४००
३७— ,,	१८ १/२ बटे ६०	५,५५०
३८— ,,	१९/६०	५,७००
३९— ,,	१९ १/२ बटे ६०	५,८५०
४०— ,,	२०/६०	६,०००
४१— ,,	२० १/२ बटे ६०	६,१५०
४२— ,,	२१/६०	६,३००
४३— ,,	२१ १/२ बटे ६०	६,४५०
४४— ,,	२२/६०	६,६००
४५— ,,	२२ १/२ बटे ६०	६,७५०
४६— ,,	२३/६०	६,७५०
४७— ,,	२३ १/२ बटे ६०	६,७५०
४८— ,,	२४/६०	६,७५०
४९— ,,	२४ १/२ बटे ६०	६,७५०
५०— ,,	२५/६०	६,७५०
५१— ,,	२५ १/२ बटे ६०	६,७५०
५२— ,,	२६/६०	६,७५०
५३— ,,	२६ १/२ बटे ६०	६,७५०
५४— ,,	२७/६०	६,७५०
५५— ,,	२७ १/२ बटे ६०	६,७५०
५६— ,,	२८/६०	६,७५०
५७— ,,	२८ १/२ बटे ६०	६,७५०
५८— ,,	२९/६०	६,७५०
५९— ,,	२९ १/२ बटे ६०	६,७५०
६०— ,,	३०/६०	६,७५०
तथा अधिक		

प्रपत्र "क"

मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपादान के हेतु नामांकन

यदि अधिकारी के परिवार हो और वह उसके किसी एक सदस्य को नामांकित करना चाहे :—

मैं इस नामांकन-पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्ति को, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, नामांकित करता हूँ तथा उसे उपर्युक्त उपादान को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जिसे मेरी महापालिका की सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में मुख्य नगर अधिकारी स्वीकृत करें तथा मेरी मृत्यु के बाद उस उपादान को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जो मुझे मेरे सेवा-निवृत्त होने पर प्राप्य हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय प्राप्य रह जाय :—

नामांकित व्यक्ति का नाम व पता	अधिकारी से सम्बन्ध	आयु	वे अवस्थायें जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जायगा
१	२	३	४

उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के नाम (यदि कोई हो) और उनका पता तथा सम्बन्ध, जिन्हें नामांकित व्यक्ति का अधिकारी से पूर्व मृत्यु होने पर, नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होंगे अथवा नामांकित व्यक्ति की अधिकारी की मृत्यु के बाद उपादान का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा :	उपादान का धन अथवा भाग जो प्रत्येक को देय होगा।
५	६

यह नामांकन मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक ..... को किये गये नामांकन को अब रद्द करता है

दिनांक..... माह..... सन् १९७ ई० को ..... स्थान .....में नामांकन किया।

साक्षी :—

(१)..... .....

(२)..... .....

अधिकारी के हस्ताक्षर

यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जावेगा जिससे उपादान का पूरा धन बट जाय

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने को)

..... पद ....कार्यालय..... .. ..के द्वारा नामांकित

दिनांक..... ....(विभागीय अधिकारी) हस्ताक्षर..... .....

पद ....

प्रपत्र "ख"

मृत्यु एवं सेवा-निवृत्त उपादान)डेथ कम पेन्शन ग्रेच्युटी) के हेतु नामांकन

जब अधिकारी के परिवार हो तथा वह उसके एक से अधिक सदस्यों को नामांकित करना चाहें :—

मैं इस नामांकन-पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, नामांकित करता हूँ तथा उन्हें नीचे लिखे अनुसार उस उपादान को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जिसे मेरी महापालिका की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की दशा में मुख्य नगर अधिकारी स्वीकृत करें तथा मेरी मृत्यु के बाद उस उपादान को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जो मुझे मेरे सेवा निवृत्त होने पर प्राप्य हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय प्राप्य रह जाय।

नामांकित व्यक्तियों के नाम व पते	अधिकारी से सम्बन्ध (रिश्ते)	आयु	उपादान का धन अथवा भाग जो प्रत्येक को देय होगा	वे अवस्थायें जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जायगा
१	२	३	४	५

उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के नाम (यदि कोई हो) और उनका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति की अधिकारी से पूर्व मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होंगे अथवा नामांकित व्यक्ति के अधिकारी की मृत्यु के बाद उपादान का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा	उपादान का धन, अथवा भाग जो प्रत्येक को देय होगा

यह नामांकन मेरे द्वारा इससे पूर्व ..... को किये गये नामांकन को रद्द करता है।

टिप्पणी – प्राधिकारी के इस प्रपत्र में लिखी गई अन्तिम पंक्ति के नीचे के खाली स्थान को लकीर खींचकर निष्प्रयोज्य कर देना चाहिए जिससे उनके हस्ताक्षर करने के बाद इसमें कुछ लिखा न जा सके।

दिनांक..... माह ..... सन् १९७ ई० को ..... बजे ..... स्थान ..... में नामांकित किया।

साक्षी—

१.....

२.....

अधिकारी के हस्ताक्षर

इस स्तम्भ में भरा गया धन/भाग इस तरह भरा जाना चाहिए जिससे उपादान का पूरा धन/भाग विभाजित हो जाय।

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने को)

दिनांक..... पद..... .....कार्यालय ..... के द्वारा नामांकित।

हस्ताक्षर .....

पद .....

प्रपत्र "ग"

मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपादान हेतु नामांकन

जब अधिकारी के परिवार न हो और वह किसी व्यक्ति को नामांकित करना चाहे :—

मेरे कोई परिवार नहीं है। मैं इस प्रमाण-पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्ति को नामांकित करता हूँ तथा उसे उस उपादान के प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जिसे मेरी महापालिका की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की दशा में मुख्य नगर

अधिकारी स्वीकृत करें तथा मेरी मृत्यु के बाद उस उपादान को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जो मुझे मेरे सेवा-निवृत्ति होने पर प्राप्त हो और मुझे मेरी मृत्यु के समय प्राप्य रह जाय :—

नामांकित व्यक्ति का नाम व पता	अधिकारी से सम्बन्ध	आयु	वे अवस्थायें जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जायगा	उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों का नाम (यदि कोई हो) और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होंगे अथवा नामांकित व्यक्ति के अधिकारी की मृत्यु के बाद उपादान का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा	उपादान का धन अथवा भाग जो प्रत्येक को देय होगा
१	२	३	४	५	६

यह नामांकन मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक .....को किये गये नामांकन को अब रद्द करता है ।

दिनांक..... .....माह..... ....सन् ....को..... .....

स्थान .... में नामांकन किया ।

साक्षी—

(१) ....

(२) ....

अधिकारी के हस्ताक्षर

यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जावेगा जिससे उपादान का पूरा धन बट जाय ।

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने को)

.... पद..... .....कार्यालय..... ....के द्वारा नामांकित ।

हस्ताक्षर..... ....

पद..... ....

दिनांक

(विभागीय अधिकारी

प्रपत्र "ध"

मृत्यु सम्मिलित सेवा-निवृत्ति उपादान हेतु नामांकन

यदि अधिकारी के परिवार न हो और वह एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करना चाहे :—

मेरे परिवार नहीं है। मैं निम्नांकित व्यक्तियों को नामांकित करता हूँ तथा उन्हें नीचे लिखे अनुसार उस उपादान को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जिसे मेरी महापालिका की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की दशा में मुख्य नगर अधिकारी स्वीकृत करें तथा मेरी मृत्यु के बाद उस उपादान को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जो मुझे मेरे सेवा-निवृत्त होने पर प्राप्य हो जो मुझे मेरी मृत्यु के समय प्राप्य रह जाय।

नामांकित व्यक्तियों का नाम व पता	अधिकारी से सम्बन्ध (रिश्ता)	आयु	उपादान का धन अथवा भाग जो प्रत्येक को देय होगा	वे अवस्थायें जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जायगा	उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम (यदि कोई हो) और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्य होंगे अथवा नामांकित व्यक्ति के अधिकारी की मृत्यु के बाद उपादान का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा
१	२	३	४	५	६

उपादान धन अथवा भाग जो प्रत्येक को देय होगा

यह नामांकन मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक ..... को किये गये नामांकन को अभ रंद करता है।

टिप्पणी—अधिकारी के इस प्रपत्र में लिखी गई अन्तिम पंक्ति के नीचे के खाली स्थान में लकीर खींचकर निष्प्रयोग कर देना चाहिए जिससे उसके हस्ताक्षर करने के बाद में इसमें कुछ लिखा न जा सके।

दिनांक ..... माह ..... सन् १९७ ई० को..... बजे ..... स्थान .....में मामांकित किया।

साक्षी—

१.... ....

२ ....

अधिकारी के हस्ताक्षर

इस स्तम्भ में भरा गया धन/भाग इस तरह भरा जाना चाहिए जिससे उपादान का पूरा धन/भाग विभाजित हो जाय।

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने को)

....पद . ... कार्यालय .... के द्वारा नामांकित।

हस्ताक्षर.... ....

दिनांक .... पद ....

प्रपत्र 'ड.''

पारिवारिक निवृत्ति वेतन के लिये नामांकन

मैं इस प्रमाण-पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, अधोलिखित क्रम में उस पारिवारिक निवृत्ति वेतन और जीवन काल के कुल बकाया धन का भुगतान को पाने के लिए नामांकित करता हूँ जिसे मुख्य नगर अधिकारी मेरी १० वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर मृत्यु की दशा में स्वीकृत करें।

नामांकित व्यक्ति का नाम व पता	अधिकारी से सम्बन्ध	आयु	विवाहित अथवा अविवाहित
१	२	३	४

यह नामांकन मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक ....को किये गये नामांकन को अब रद्द करता है।

टिप्पणी—अधिकारी को इस प्रपत्र में लिखी गई अन्तिम पंक्ति के नीचे के खाली स्थान को लकीर खींचकर निष्प्रयोग कर देना चाहिये जिससे उसके हस्ताक्षर करने के बाद इसमें कुछ लिखा न जा सके।

दिनांक ..... माह ..... सन् ..... को .....

स्थान ..... में नामांकित किया ।

साक्षी :—

(१) .....

(२) .....

अधिकारी के हस्ताक्षर

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने के लिये)

..... पद ..... कार्यालय ..... के द्वारा नामांकित

दिनांक ..... हस्ताक्षर .....

पद .....

(विभागीय अधिकारी)

प्रपत्र "च"

सेवा अधिकारी को सेवा-निवृत्ति वेतन और उपादान स्वीकृति के लिए विभागीय अधिकारी द्वारा भेजे जाने वाले लेख-पत्रों की तालिका—

१—सेवा-निवृत्ति वेतन और उपादान स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र (मुख्य नगर अधिकारी द्वारा निर्धारित फार्म में) ।

२—अशक्तता का प्रमाण-पत्र (यदि अशक्तता के कारण पेन्शन माँगी जाती हो) ।

३—सेवा-पुस्तिका पूरी करके ।

४—औसत उपलब्धियों का विवरण ।

५—अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र ।

६—(क) साक्षीकृत दो नमूने के हस्ताक्षर (अटेस्टैड स्पेसीमेन सिगनेचर) ।

(ख) दो स्लिप जिन पर बायें हाथ के अंगूठे व अंगुलियों के साक्षीकृत चिन्ह हों तथा साक्षीकृत पासपोर्ट साइज फोटो ।

७—किसी अन्य पेन्शन व ग्रेच्युटी न पाने का पेन्शनर का घोषणा-पत्र ।

सेवा अधिकारी—

ऊपर दिये हुए कागजात ..... पद की पेन्शन अथवा/और उत्पादन स्वीकृत करने के लिए भेजे जा रहे हैं । कृपया इन्हें चैक करके आगे की कार्यवाही करें ।

(विभागीय अधिकारी)

नगर महापालिका, आगरा

प्रपत्र "छ"

सेवा निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका संख्या.....

(सेवा निवृत्ति पाने वाले अधिकारियों के लिए)

बजट मद जिससे देय ... ...

निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्त्ता का नाम ... .

पिता का नाम ....

पद जिससे सेवा निवृत्ति हुये .. ..

निवृत्ति वेतन का प्रकार तथा स्वीकृत आदेश की संख्या व दिनांक	जन्म तिथि	जाति
१	२	३

निवास स्थान का पता	मासिक निवृत्ति वेतन का धनांक	टिप्पणी
४	५	६

लेखा अधिकारी

आगामी नोटिस तक प्रत्येक मास के समाप्त होने पर आप श्री .... पुत्र/पत्नी श्री .... को रु० .... पै० (शब्दों में) .... इन्कम टैक्स काट कर उनकी सेवा निवृत्ति वेतन एक बार में इस आदेश तथा निर्धारित फार्म पर रसीद प्रस्तुत करने पर भुगतान करें। यह भुगतान दिनांक .... से प्रारम्भ होगा।

हस्ताक्षर ....

मुख्य नगर अधिकारी, प्रशासक

टिप्पणी (१)—इस आदेश द्वारा देय पेन्शनें निम्न दशाओं के अतिरिक्त प्रत्येक पेन्शनर को प्रपत्र "ज" में जीवित होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु लेखाधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना आवश्यक है :—

(क) उन व्यक्तियों को जो बीमारी अथवा शारीरिक अशक्ति के कारण स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हों, वे यदि प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी से आदेश प्राप्त कर लें तो किसी वरिष्ठ महापालिका अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति जिसे इस प्रयोजन हेतु प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी प्राधिकृत कर दें, के द्वारा सम्बन्धित पेन्शनर के जीवित होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पेन्शनर की स्वर्य की पावती पर उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को भुगतान किया जावेगा।

(ख) उन व्यक्तियों को जो आगरा से बाहर हों किसी राजपत्रित अधिकारी/संसद सदस्य/विधायक से जीवित होने का प्रमाण पत्र सहित प्रार्थना-पत्र स्पष्ट विकल्प के साथ कि धनराशि क्रास्ड चैक/क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट/धनादेश (मनीआर्डर) में से किस माध्यम से भेजी जाय, प्राप्त होने पर पेन्शनर की स्वयं की जिम्मेदारी पर क्रास्ड चैक/क्रास्ड ड्राफ्ट/धनादेश द्वारा भेजने में जो भी व्यय हो, उसे पेन्शनर को देय धनराशि में से काटकर शेष धनराशि उसके पास भेजदी जावेगी। इस प्रकार भुगतान होने में किसी भी गलत हस्तांन्तरण के लिए महापालिका का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(ग) ऊपर की क तथा ख प्रत्येक दशा में पेन्शनर को वर्ष में कम से कम एक बार उपरोक्त जीवन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त जीवित होने के सबूत के रूप में लेखाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना आवश्यक होगा।

(२) पेन्शनर की मृत्यु होने पर उसके परिवार को इस आदेश पत्रिका को पेन्शनर की मृत्यु के दिनांक को सूचित करते हुए मुख्य नगर अधिकारी को तुरन्त लौटा देना चाहिए :—

सेवा निवृत्ति वेतन का धनांक ... .

लेखाधिकारी द्वारा प्रत्येक पृथक भुगतान नीचे लिखा जाना चाहिए :—

मास जिसका सेवा निवृत्ति वेतन देय है।	१९		
मार्च से फरवरी	भुगतान का दिनांक व वाउचर संख्या	.....	लेखाधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट

आगरा नगर महापालिका कर्मचारी सेवा निवृत्ति वेतन तथा उपादान नियमावली १९६२ मूल रूप में विज्ञप्ति सं० २६१ जी० डी० एकाउन्ट्स दिनांक २८ दिसम्बर १९६४ द्वारा उत्तर प्रदेश के राजपत्र में दिनांक ९ जनवरी, १९६५ में प्रकाशित हुए। इसके पश्चात् इसमें समय-समय पर जो संशोधन हुए वे निम्न प्रकार हैं :—

(१) प्रथम संशोधन उत्तर प्रदेश के राजपत्र के भाग ३ में दिनांक २३ अप्रैल १९६६ में प्रकाशित हुआ।

विज्ञप्ति सं० ४१ जी० डी० एच० ओ० दि० १५ अप्रैल १९६६

आगरा नगर महापालिका कर्मचारी सेवा निवृत्ति वेतन तथा उपादान नियमावली, १९६२ में, जो कार्यकारिणी समिति नगर महापालिका, आगरा में उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४८ (१) (च) के अन्तर्गत बनाये थे तथा जिनकी आगरा नगर महापालिका ने पुष्टि की थी और जो उत्तर प्रदेश गजट के भाग ३ में दिनांक ९ जनवरी, १९६५ को प्रकाशित हुये थे, निम्न संशोधन, प्रशासक, नगर महापालिका ने किया है जो अधिनियम की धारा ५४८ (३) के अन्तर्गत प्रकाशित किया जाता है।

संशोधन

नियम १ (२) के अन्त में शब्द "प्रकाशन तिथि के ६ माह के अन्दर" के स्थान पर शब्द "३० अप्रैल, १९६६ तक" पढ़ा जाय।

(२) द्वितीय संशोधन उत्तर प्रदेश के राजपत्र के भाग ३ में दिनांक ८ अप्रैल १९६७ में प्रकाशित हुआ।

विज्ञप्ति सं० ५२१ जी० डी० एच० ओ० दि० ३० मार्च १९६७

आगरा नगर महापालिका कर्मचारी सेवा निवृत्ति वेतन तथा उपादान नियमावली १९६२ में जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४८ (१) (च) के अन्तर्गत बनाये गये थे तथा जो उत्तर प्रदेश गजट के भाग ३ में दिनांक ९ जनवरी, १९६५ को प्रकाशित हुये थे, निम्न संशोधन प्रशासक, नगर महापालिका ने किये हैं जो अधिनियम की धारा ५४८ (३) के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाते हैं :—

संशोधन

(१) नियम ३(२) (ख) के अन्त में तथा उसके नीचे दिये स्पष्टीकरण में निम्न प्रतिबन्ध और जोड़ा जाये :—

"प्रतिबन्ध यह है कि विनियम संख्या ३ (२) (ख) में वर्णित ३ माह की अवधि को मुख्य नगर अधिकारी किसी भी विशेष परिस्थिति में हटा सकते हैं।"

(२) नियम ८ के अन्त में "मृत्यु" शब्द के पश्चात पूर्णविराम के स्थान पर अर्द्ध विराम रखा जाय और उसके आगे निम्न जोड़ा जाये :—

"प्रपत्र 'ङ' में पारिवारिक निवृत्ति वेतन को पाने के लिए अधिकृत व्यक्ति को जीवनकाल के कुल बकाया धन का भुगतान किया जाये"

प्रपत्र 'ङ' की दूसरी लाइन में शब्द 'पारिवारिक निवृत्ति वेतन" के बाद निम्न और जोड़ा जाये :—

"और जीवनकाल के कुल बकाया धन का भुगतान"

(३) विनियम १२ (२) में शब्द "५० रुपये" के स्थान पर "१५० रुपया" पढ़ा जाये।

(३) तृतीय संशोधन उत्तर प्रदेश के राजपत्र के भाग ३ में दिनांक १४ अक्टूबर १९६७ में प्रकाशित हुआ।

विज्ञप्ति सं० १०६६ जी० डी० एच० ओ० दि० ३ अक्टूबर १९६७

आगरा नगर महापालिका कर्मचारी सेवा निवृत्ति वेतन तथा उपादान नियमावली १९६२ में जो कार्यकारिणी समिति नगर महापालिका, आगरा ने उत्तर प्रदेश नगर महापालिका, अधिनियम, १९५९ की धारा ५४८ (१) (च) के अन्तर्गत बनाये थे तथा जिनकी आगरा नगर महापालिका ने पुष्टि की थी और जो उत्तर प्रदेश गजट के भाग ३ में दिनांक ९ जनवरी, १९६५ को प्रकाशित हुये थे, निम्न संशोधन प्रशासक, नगर महापालिका ने किया है, जो अधिनियम की धारा ५४८ (३) के अन्तर्गत प्रकाशित किया जाता है :—

संशोधन

नियम १ (२) के अन्त में शब्द "३० अप्रैल, १९६६ तक" के स्थान पर शब्द "२९ फरवरी, १९६८ तक" पढ़ा जाय।

(४) चतुर्थ संशोधन उत्तर प्रदेश के राजपत्र के भाग ३ में दिनांक २ मार्च १९६८ में प्रकाशित हुआ।

विज्ञप्ति सं० ४६०/पी० एफ०/एकाउण्ट्स (वि०) दिनांक १६-२-१९६८

आगरा नगर महापालिका कर्मचारी सेवा निवृत्ति वेतन तथा उपादान नियमावली, १९६२ में जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४८ (१) (च) के अन्तर्गत बनाये गये थे तथा जो उत्तर प्रदेश गजट के भाग ३ में दिनांक ९ जनवरी १९६५ को प्रकाशित हुये थे, निम्न संशोधन प्रशासक, नगर महापालिका आगरा ने किया है जो अधिनियम की धारा ५४८ (३) के अन्तर्गत प्रकाशित किया जाता है।

संशोधन

नियम ७ के अन्त में निम्न और जोड़ा जाये :—

"पेन्शन की धनराशि पूरे रुपयों में अभिव्यक्त की जायेगी और जहाँ भी नियमानुसार गणना करने पर पेन्शन में रुपये से कम कोई धनराशि हो, तो वह अगले पूर्ण रुपये में बदल दी जायेगी।"

(५) पंचम संशोधन — उत्तर प्रदेश के राजपत्र के भाग ३ में दिनांक २७ अप्रैल १९७४ में प्रकाशित हुआ।

विज्ञप्ति सं० ५३/डी०एफ०-पी०एफ-एस दि० १९-४-७४

आगरा नगर महापालिका कर्मचारी सेवा-निवृत्ति वेतन तथा उपादान नियमावली १९६२ में, जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४८ (१) (च) के अन्तर्गत बनाए गये थे तथा जो उत्तर प्रदेश गजट के भाग ३ में दिनांक ९ जनवरी, १९६५ को प्रकाशित हुये थे, निम्नांकित संशोधन प्रशासक नगर महापालिका आगरा ने किये हैं जिनको अधिनियम की धारा ५४८ (३) के अन्तर्गत प्रकाशित किया जाता है :--

संशोधन

१–विनियम २ (८) (२) के अन्त में जोड़ी जाय :–
"चाहे उसका भविष्य निधि काटा गया हो अथवा न काटा गया हो।"

२–विनियम २ (९) में सेवा निवृत्ति की 'परिभाषा' में "सेवा अवधि पूर्ण करने पर" के बाद, "स्थायी रूप से पूर्णतया अशक्त हो जाने पर" जोड़ दिया जाय।

३–विनियम २ (९) के नीचे निम्नांकित स्पष्टीकरण जोड़ा जाये :–
स्पष्टीकरण–विनियम २ (९) में विहित 'स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति' का तात्पर्य है कि पचास वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अथवा पच्चीस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेने पर कोई अधिकारी कर्मचारी या सेवक स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति हेतु प्रार्थना कर सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि जिस तिथि से वह स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति चाहता है उसके तीन माह पूर्व उसे तद्अर्थ मुख्य नगर अधिकारी को नोटिस देना होगा तथा पूर्णतया अशक्त हो जाने पर किसी अधिकारी को मुख्य नगर अधिकारी द्वारा आवश्यक जाँच के पश्चात् तीन माह का नोटिस देकर सेवा निवृत्त किया जा सकता है।

४–विनियम १२ (१) में निम्नांकित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय–
"प्रतिबन्ध यह रहेगा कि सेवा निवृत्ति के बाद उपादान की सम्भावित धनराशि का एवं सेवा निवृत्ति वेतन की सम्भावित धनराशि का दो तिहाई भाग लेखा अधिकारी की जाँच के पश्चात् परन्तु मुख्य नगर लेखा परीक्षक की जाँच के पूर्व भी अग्रिम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जिसको उपादान एवं सेवा निवृत्ति वेतन के अन्तिम रूप से निर्धारण होने पर कुल देय धनराशि में से काट कर समायोजित कर लिया जायगा।"

५–वर्तमान विनियम ९ (१) के स्थान पर निम्नांकित संशोधित विनियम रखा जाय :–

"६ (१) -- प्रत्येक अधिकारी जो सेवा निवृत्ति वेतन के योग्य पन्द्रह वर्षों की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवा निवृत्ति होने पर अथवा सेवा में रहते हुए मृत हो जाय तो उसके परिवार को नीचे के उप विनियम (२) में वर्णित धनराशि से अधिक न होते हुए पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन उसकी विधवा पत्नी को आजीवन या जब तक वह पुनर्विवाह न करे अथवा परिवार के अन्य किसी सदस्य को प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अन्तर्गत रहते हुए अधिक से अधिक दस वर्ष तक दिया जायगा। प्रतिबन्ध यह है कि पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन भुगतान की अवधि विधवा पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी दशा में मृत्यु यदि सेवा निवृत्ति होने के बाद हो तो उस दिनांक से जब सम्बन्धित अधिकारी सेवा अवधि पूर्ण होने पर सेवा निवृत्ति हुआ हो या होता अथवा यदि मृत्यु सेवा में रहते हुए हो तो उस दिनांक से जब वह साधारण अवस्था में सेवा अवधि पूर्ण कर निवृत्ति वेतन प्राप्त कर सेवा निवृत्ति होता, पाँच वर्ष से अधिक न होगी।

ये संशोधन सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होंगे, तथा उन सेवा निवृत्ति कर्मचारियों पर भी प्रभावी होंगे जिनके मामले अभी तक अनिर्णीत हैं।

(६) षष्ठम संशोधन उत्तर प्रदेश के राजपत्र के भाग ३ में दिनांक १५ नवम्बर १९६५ में प्रकाशित हुआ।

विज्ञप्ति सं० ६५ डी० एकाउन्ट पी० एफ० एस० दि० १२-८-६५

आगरा नगर महापालिका कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमेन्ट बैनीफिट) विनियम, १९६२ में, जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४८ (१) (च) के अन्तर्गत बनाये गये थे तथा जो उत्तर प्रदेश गजट के भाग ३ में दिनांक ९ जनवरी, १९६५ को विज्ञप्ति संख्या २९१ जी० डी० एकाउन्ट्स, दिनांक २८ दिसम्बर, १९६४ द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर संशोधित हुए, में निम्नलिखित संशोधन प्रशासक, नगर महापालिका, आगरा ने किये हैं, जिनको अधिनियम की धारा ५४८ (३) के अन्तर्गत प्रकाशित किया जाता है :—

संशोधन

विनियम संख्या २ (२)—औसत उपलब्धियों की परिभाषा में शब्द "से पूर्व" तथा "मास में" के बीच उपलब्ध संख्या ३६ के स्थान पर १२ तथा इसी प्रकार शब्द 'यदि इन' तथा 'मासों के' बीच उपलब्ध संख्या ३६ के स्थान पर १२ पढ़ा जाय :—

विनियम संख्या २ (८)—वर्तमान विनियम संख्या २ (८) के उपबन्ध के स्थान पर निम्न प्रकार संशोधित उपबन्ध पढ़ा जाय :—

उपबन्ध यह है कि नगरपालिका, जिला परिषद, नगर सुधार प्रन्यास, छावनी बोर्ड अथवा नगर महापालिका में

(१) कार्य से भारित अधिष्ठान (चार्ज ऐस्टेब्लिशमेंट) की सेवा अवधि,

(२) आकस्मिक निधि (कन्टिजेन्सी) से देय पारिश्रमिक वाले पद पर कार्य की सेवा अवधि; तथा

(३) पदच्युति (डिसमिसल), निष्कासन (रिमूवल) तथा त्याग-पत्र (रेजीग-नेशन) के फलस्वरूप व्याघातित (इन्टरप्टेड) सेवा के अतिरिक्त,

किसी एक पद अथवा अन्य पद पर स्थायी, अस्थायी अथवा स्थानापन्न सेवा भी अर्हकारी सेवा समझी जावेगी, चाहे उसका भविष्य निधि काटा गया हो अथवा न काटा गया हो।

विनियम संख्या ९–वर्तमान विनियम संख्या ९ के प्रथम अनुच्छेद के स्थान पर प्रतिबन्धात्मक अनुच्छेद से पूर्व निम्नलिखित संशोधित विनियम पढ़ा जाय :–

९–प्रत्येक अधिकारी जिसे इन विनियमों के विनियम ७ के अन्तर्गत निवृत्ति वेतन मिलता है, उसे उस विनियम के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले निवृत्ति वेतन की धनराशि का १/३ भाग तक किसी भाग के सरांशी-करण (कम्यूटेशन) कराने का अधिकार होगा तथा इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सिविल पशन कम्यूटेशन रूल्स इस प्रतिबन्ध के साथ लागू होंगे कि उक्त कम्यूटेशन रूल्स के नियम १८ के तात्पर्य के लिए प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, चिकित्सा परिषद् का गठन करेंगे। जिसके लिए चिकित्सा अधिकारियों को नामोद्दिष्ट (नामीनेट) करेंगे तथा नियम २२ के अनुसार देय कुल शुल्क (टोटल फी) प्रार्थी द्वारा महापालिका निधि में जमा की जावेगी जब तक कि प्रशासक/मुख्य नगर-अधिकारी राज्य सरकार की स्वीकृति से शुल्क के किसी भाग को चिकित्सा परिषद् के सदस्यों या चिकित्सा अधिकारी को देना न निश्चित करें।

विनियम संख्या १२ (१)—वर्तमान विनियम १२ (१) के प्रतिबन्धात्मक अनुच्छेद के अन्तिम वाक्य के बाद निम्न वाक्य जोड़ दिया जाये :–

"किन्तु उक्त उपादान एवं सेवा निवृत्ति की सम्भावित धनराशि के दो तिहाई भाग के भुगतान से पूर्व सम्बन्धित कार्यकारी को निम्नांकित प्रपत्र में एक घोषणा पत्र देना होगा।"

घोषणा पत्र का प्रारूप

चूँकि प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, आगरा मुझे देय सेवा निवृत्ति वेतन उपादान तथा सेवा निवृत्ति वेतन का सही धन निर्धारित किये जाने और उसकी आवश्यक जाँच की पूर्ति की प्रत्याशा में सेवा निवृत्ति वेतन उपादान की सम्भावित धनराशि में से रु० ..... शब्दों (..... रु० मात्र) और सेवा निवृत्ति वेतन की सम्भावित मासिक धनराशि में से रु० ..... शब्दों (..... रुपया मात्र) अग्रिम रूप से अन्तःकालीन भुगतान करने के लिए सहमत हो गये हैं। अतः मैं इस लेख द्वारा स्वीकार करता हूँ कि उपादान और सेवा निवृत्ति वेतन के मासिक अग्रिम (एडवान्स) के ग्रहण करने

में मैं पूरी तरह यह समझता हूँ कि यह मुझे देय सेवा निवृत्ति उपादान और सेवा निवृत्ति वेतन की आवश्यक यथाविधि जाँच पूरी होने पर संशोधनीय है और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस संशोधन में मैं इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं करूँगा कि प्रत्याशित सेवा निवृत्ति उपादान या मासिक सेवा निवृत्ति वेतन जो इस समय मुझे भुगतान किया जा रहा है, उस सेवा निवृत्ति उपादान या/और मासिक सेवा निवृत्ति वेतन से अधिक है जो अन्तिम रूप से मुझे स्वीकार किया जावेगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि सेवा निवृत्ति उपादान और मासिक सेवा निवृत्ति वेतन का जो धन अन्तिम रूप से स्वीकार किया जावे, उससे अधिक जो भी भुगतान मुझे होगा मैं तुरन्त लौटा दूँगा :-

साक्षी :—

१- नाम ..... हस्ताक्षर .....

पता ..... दिनांक .....

२- नाम ..... पता .....

पता ..... स्टेशन .....

नोट-अनावश्यक शब्द काट दीजिए।

विनियम संख्या १२ (२)-वर्तमान विनियम संख्या १२ (२) के अन्त में निम्न और जोड़ दिया जाय :-

निम्न दशाओं के अतिरिक्त प्रत्येक पेन्शनर को प्रपत्र "ज" में जीवित होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु लेखाधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना आवश्यक है :-

(क) उन व्यक्तियों को जो बीमारी अथवा शारीरिक अशक्ति के कारण स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हों, वे यदि प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी से आदेश प्राप्त कर लें तो किसी वरिष्ठ महापालिका अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति जिसे इस प्रयोजन हेतु प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी प्राधिकृत कर दे, के द्वारा सम्बन्धित पेन्शनर के जीवित होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पेन्शनर की स्वयं की पावती पर उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को भुगतान किया जावेगा।

(ख) उन व्यक्तियों को जो आगरा से बाहर हों, किसी राजपत्रित अधिकारी/संसद सदस्य/विधायक से जीवित होने का प्रमाण-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र स्पष्ट विकल्प के साथ कि धनराशि क्रास्ड चैक/क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट/धनादेश (मनी आर्डर) में से किस माध्यम से भेजी जाय, प्राप्त होने पर पेन्शनर की स्वयं की जिम्मेदारी पर क्रास्ड चैक/क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट/धनादेश द्वारा भेजने में जो भी व्यय हो, उसे पेन्शनर को देय पेन्शन में से कटौती कर शेष धनराशि उसके पास भेज दी जावेगी। इस प्रकार भुगतान [illegible] गलत हस्तान्तरण के लिए महापालिका का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(ग) ऊपर की [illegible] में पेन्शनर को वर्ष में कम से कम एक बार उपरोक्त शीर्षक [illegible] प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त जीवित होने के सबूत के रूप में लेखाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना आवश्यक होगा।

उपरोक्त शर्तों के अनुसार प्रपत्र 'छ' की टिप्पणी नं० १ में भी संशोधन कर दिया है। संशोधित प्रपत्र "छ" संलग्न है।

विनियम संख्या १३-बनियम १३ में प्रथम अनुच्छेद के अन्तिम शब्द "पड़ेगी" के उपरान्त निम्न पंक्तियां बढ़ा दी जावें :-

"जब तक कि वे इसमें किसी परिवर्तन का प्रार्थना-पत्र मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षक जैसी भी स्थिति हो, को किसी वर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह में न दें अगले वर्ष के लिए वही दर बनी रहेगी तथा वर्ष के बीच में दर में कोई परिवर्तन स्वीकृत न किया जायेगा।"

वर्तमान विनियम संख्या २० के स्थान पर निम्न प्रकार संशोधित विनियम पढ़ा जाय :-

संशोधित विनियम २०--

२०-किसी अधिकारी के खाते में सामान्य भविष्य निधि में जमा धन उसके महापालिका की सेवा से निवृत्ति होने पर उसे लौटा दिया जायगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी/कर्मचारी चाहे तो सामान्य भविष्य निधि में अपने खाते में साधारणतः जमा धन के आधे से अनधिक धन को या उसके ६ माह के वेतन तक इसमें से जो भी कम हो, २३ वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अथवा सेवा पूर्ण होने से १० वर्ष पूर्व अपने निवास के लिए मकान बनाने, क्रय करने, मरम्मत करने या इस सम्बन्ध में लिये गये ऋण को अदा करने अथवा अपनी लड़की या लड़के के विवाह करने व अपने आश्रित बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने हेतु एक मोटर कार क्रय करने या उक्त प्रयोजन से पहले ही लिये गये ऋण को प्रतिदान करने हेतु मुख्य नगर अधिकारी/प्रशासक की स्वीकृति से अन्तिम निष्कासन ले सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत करने वाले अधिकारी को यह क्षमता होगी कि वह सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि का ३/४ भाग तक के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति प्रदान कर दें।

उपरोक्त धन निकालने के ६ माह के भीतर मुख्य नगर अधिकारी को सन्तोष दिलाना होगा कि धन उस कार्य में, जिसके लिये वह निकाला गया था, प्रयोग कर लिया गया है। ऐसा न करने पर अग्रिम लिया धन मुख्य नगर अधिकारी को सामान्य भविष्य निधि में उसके खाते में जमा करने के लिये लौटा देना होगा। यदि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी मुख्य नगर अधिकारी को व्यय के विषय में सन्तोष न दिला सके अथवा बचा हुआ धन न लौटाये तो मुख्य नगर अधिकारी वह धन उसके वेतन से उचित किस्तों में वसूल कर लेने के लिये सक्षम होंगे।

यह संशोधन उत्तर प्रदेश शासन के राज पत्र (शासकीय गजट) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे तथा उन सेवा निवृत्त कर्मचारियों पर भी प्रभावी होंगे जिनके मामले उक्त दिनांक तक अनिर्णीत हैं।

आगरा नगर महापालिका

प्रपत्र "छ"

सेवा निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका संख्या.....

(सेवा निवृत्ति पाने वाले अधिकारियों के लिए)

बजट मद जिससे देय .....

निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्त्ता का नाम .....

पिता का नाम .....

पद जिससे सेवा निवृत्ति हुए.....

निवृत्ति वेतन का प्रकार तथा स्वीकृति आदेश संख्या व दिनांक	जन्म तिथि	जाति
१	२	३

निवास स्थान का पता	मासिक निवृत्ति वेतन का धनांक	टिप्पणी
४	५	६

लेखा अधिकारी,

आगामी नोटिस तक प्रत्येक मास के समाप्त होने पर आपश्री ..... पुत्र/पत्नी श्री ..... को रु० ..... (शब्दों में) ..... रु० (इन्कम टैक्स काट कर) उनकी सेवा निवृत्ति वेतन एक बार में इस आदेश तथा निर्धारित फार्म पर रसीद प्रस्तुत करने पर भुगतान करें। यह भुगतान दिनांक ..... से प्रारम्भ होगा।

हस्ताक्षर

मुख्य नगर अधिकारी/प्रशासक

टिप्पणी (१)—इस आदेश द्वारा दत्त पेन्शन निम्न दशाओं के अतिरिक्त प्रत्येक पेन्शनर को पत्र 'ज' में जीवित होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु लेखाधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना आवश्यक है :

(क) उन व्यक्तियों को जो बीमारी अथवा शारीरिक अशक्ति के कारण स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हों, वे यदि प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी से आदेश प्राप्त करें तो किसी वरिष्ठ महापालिका अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति जिसे इस प्रयोजन हेतु प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी प्राधिकृत करें, के द्वारा सम्बन्धित पेन्शनर के जीवित होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पेन्शनर की स्वयं की पावती पर उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को भुगतान किया जावेगा।

(ख) उन व्यक्तियों को जो आगरा से बाहर हों किसी राजपत्रित अधिकारी/संसद सदस्य/विधायक से जीवित होने का प्रमाण-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र स्पष्ट विकल्प के साथ कि धनराशि क्रास्ड चैक/बैंक ड्राफ्ट क्रास्ड/धनादेश (मनी आर्डर) में से किस माध्यम से भेजी जाय, प्राप्त होने पर पेन्शनर की स्वयं की जिम्मेदारी पर क्रास्ड चैक/क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट/धनादेश द्वारा भेजने में जो भी व्यय हो, उसे पेन्शनर को देय धनराशि में से काटकर शेष धनराशि उसके पास भेज दी जावेगी। इस प्रकार भुगतान होने में किसी भी गलत हस्तान्तरण के लिए महापालिका का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(ग) ऊपर की क तथा ख प्रत्येक दशा में पेन्शनर को वर्ष में कम से कम एक बार उपरोक्त जीवन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त जीवित होने के सबूत के रूप में लेखाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना आवश्यक होगा।

(२) पेन्शनर की मृत्यु होने पर उसके परिवार को इस आदेश पत्रिका को पेन्शनर की मृत्यु के दिनांक को सूचित करते हुए मुख्य नगर अधिकारी को तुरन्त लौटा देना चाहिये :—

लेखाधिकारी द्वारा प्रत्येक पृथक भुगतान नीचे लिखा जाना चाहिए :—

मास जिसका सेवा निवृत्ति वेतन देय है	१९	
मार्च से फरवरी	भुगतान का दिनांक व वाउचर संख्या	लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर

संख्या – सा–3–1901/दस–2002–971/80

प्रेषक,

श्री आनन्द मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 30 अक्टूबर, 2002

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को अनुमन्य देयों का भुगतान समय से करने के सम्बन्ध में समय–समय पर विस्तृत आदेश निर्गत किये गये हैं। प्रशासनिक कारणों से "ग्रेच्युटी" की अनुमन्य धनराशि के समय से भुगतान न होने पर भुगतान अनुमन्य होने की तिथि से तीन माह की अवधि के बाद से ब्याज दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस संदर्भ में शासनादेश संख्या सा–3–684/दस–971/80, दिनांक 29–4–1983, शासनादेश संख्या सा–3–1776/दस–971/80 दिनांक 30–11–1984, शासनादेश संख्या सा–3–202/दस–971/80, दिनांक 6–12–1994 अर्द्धशासकीय पत्र संख्या सा–3–902/दस–99–303/99, दिनांक 28–9–1999 एवं शासनादेश संख्या सा–3–721/दस–2001–305(4)/2000, दिनांक 17–5–2001 निर्गत किये गये हैं।

2. शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि प्रायः कर्मचारियों द्वारा ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब होने पर चक्रवृद्धि ब्याज दिये जाने की मांग की जाती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रेच्युटी पर ब्याज के भुगतान की दर वही रखी गयी है, जो संगत अवधि में सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पर ब्याज की हो, किन्तु चक्रवृद्धि ब्याज दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः ग्रेच्युटी पर तीन माह से अधिक के विलम्ब पर भुगतान अवधि के नियमानुसार साधारण ब्याज का ही भुगतान अनुमन्य होगा और उसकी दर संगत अवधि में सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा धनराशि पर अनुमन्य ब्याज की दर से समान होगी।

3. अनुरोध है कि ग्रेच्युटी भुगतान पर ब्याज दिये जाने के मामलों में स्पष्ट की गयी उपरोक्त स्थिति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अन्य शर्तें पूर्व निर्गत शासनादेशों के अनुसार यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

आनन्द मिश्र, सचिव, वित्त।

Scanned with OKEN Scanner

आगरा नगर निगम, आगरा

आगरा नगर निगम कर्मचारी निवृत्ति सुविधा (रिटायरमैण्ट बैनीफ़िट) विनियम 1962 में आवश्यक संशोधन 13 नवम्बर 1999 के बजट में प्रकाशित हुये थे, में नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 543(1) (च) के अन्तर्गत निम्न संशोधन अन्य विनियमों के यथावत् रहते हुये प्रकाशित किये जाते हैं :-

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
6(1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी जो पेंशन योग्य दस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने पर अथवा सेवा में रहते हुये अथवा सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाने की दशा में विधवा पत्नी/पति, जैसी स्थिति हो या उसके न होने पर नाबालिग बच्चों को 25 वर्ष की आयु/जीविकोपार्जन क्षमता प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक अथवा पुत्री के मामलों में विवाह होने अथवा जीविकोपार्जन क्षमता प्राप्त करने तक तथा विधवा पत्नी को आजीवन पारिवारिक पेंशन देय होगी । जो पुनर्विवाह करने पर समाप्त हो जायेगी ।	6(1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी जो पेंशन योग्य दस वर्ष की अहिकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होंगे उन्हें सेवा निवृत्त पेंशन देय होगी अथवा जो कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाने की दशा में अथवा एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने जाने के बाद सेवारत रहते हुये मृत्यु हो जाने की दशा में, विधवा पत्नी/पति जैसी स्थिति हो या उसके न होने पर नाबालिग बच्चों को पच्चीस वर्ष की आयु/जीविकापार्जन क्षमता प्राप्त करने, जो भी पहले हो तक अथवा पुत्री के मामलों में विवाह होने पर अथवा जीविकोपार्जन क्षमता प्राप्त करने तक तथा विधवा पत्नी अथवा पति को आजीवन पारिवारिक पेंशन देय होगी जो पति/पत्नी जैसी भी स्थिति हो के पुनर्विवाह करने पर समाप्त हो जायेगी ।

उपरोक्त संशोधन पूर्व में किये गये संशोधन तिथि 01.11.1995 से प्रभावी समझे जावेंगे ।

उपरोक्त संशोधन नगर निगम के 30वें अधिवेशन की बैठक दिनांक 24.10.2000 के प्रस्ताव संख्या 2(1.3) के अन्तर्गत स्वीकृति किया गया ।

मुख्य नगर अधिकारी
नगर निगम, आगरा ।